

e/; i n s k e a y { ; v k / k k f j r I k o z t f u d f o r j . k i z k k y h

v / ; ; u f j i k s v z  
f n l c j 2004

I a d z I k s i k u , o a H k k s t u d k v f / k d k j v f H k ; k u  
e / ; i n s k

v/; ; u ea 'kkfey l ɫFkk, a

- संपर्क मध्यप्रदेश
- सोपान, सिवनी, मध्यप्रदेश
- वास्स, धार, मध्यप्रदेश
- स्पंदन, खण्डवा, मध्यप्रदेश
- निर्माण, मण्डला, मध्यप्रदेश
- सेंटर फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट, शिवपुरी, मध्यप्रदेश
- भोजन का अधिकार अभियान, मध्यप्रदेश

v/; ; u dk ys[ku

अभिताभ सिंह, लीना सिंह,

vkɔMkə dk fo' yʃk.k

अभिताभ सिंह, लीना सिंह, ब्रज मोहन दुवगे, दीपक कौशिक, नेहा सौचे, अर्चना रावत

Vkbfi ʌ dEi kʃtʌ

राकेश यादव, दिनेश लोधी

1.	परिचय.....	4
2.	मध्यप्रदेश .....	4
3.	अध्ययन की जरूरत .....	5
4.	अध्ययन के उद्देश्य एवं अध्ययन पद्धति.....	6
5.	अध्ययन क्षेत्र का प्रोफाइल.....	7
6.	भारत वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली.....	9
7.	राज्यों को खाद्यान का आवंटन और उठाव.....	12
8.	लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर सर्वोच्च न्यायलय.....	15
9.	खाद्यान : उपलब्धता के श्रोत एवं जरूरत का समय .....	18
10.	उचित मूल्य की दुकान और लोग .....	18
11.	वितरण प्रणाली के लाभ .....	19
12.	उचित मूल्य की दुकान से खरीद .....	19
13.	उचित मूल्य की दुकान नहीं जाना .....	23
14.	उचित मूल्य की दुकान खुलने की अवधि और समय.....	24
15.	निगरानी समितियां .....	25
16.	पंचायतों और ग्रामसभाओं की भागीदारी .....	26
17.	दुकानदार के अनुभव .....	26
18.	अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष .....	27
19.	सुझाव .....	28

# e/; çns'k ea | kołtfud forj .k ç .kkyh

## 1- ifjp;

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की गई थी। और इस लिहाज से वह सरकार द्वारा खुले बाजार पर नियंत्रण रखने का एक प्रमुख औजार थी। वर्ष 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव करते हुए इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नाम दिया गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध करवाना रहा है।

### 1-1- e/; çns'k

मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 6 करोड़ के आसपास है और इसमें से लगभग 74 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। मध्यप्रदेश में आदिवासी लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और प्रदेश की कुल जनसंख्या में लगभग 20 प्रतिशत लोग आदिवासी वर्ग से ही आते हैं। आदिवासी जनसंख्या मूल रूप से गांवों में ही निवास करती है। यह तथ्य इस बात से भी प्रमाणित होता है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश कुल आदिवासी जनसंख्या का 93 प्रतिशत भाग आज भी गांवों में निवास करता है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में 15 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति वर्ग की है और इस 15 प्रतिशत का 76 प्रतिशत हिस्सा गांवों में रहता है।

e/; çns'k dh tul ā; k dk foj .k (ग्रामीण एवं शहरी की संख्या प्रतिशत में दर्शाई गई है)			
tul ā; k	e/; çns'k	vuđ #pr tkfr	vuđ #pr tutkfr
कुल जनसंख्या	60348023	9155177	12233474
प्रतिशत	100	15 <sup>०2</sup>	20 <sup>०3</sup>
ग्रामीण जनसंख्या	74	76	94
शहरी जनसंख्या	26	24	6
l ksr % tux.kuk 2001 rkfydk & 1			

मध्यप्रदेश देश के गरीब राज्यों की श्रेणी आता है और योजना आयोग के वर्ष 1999–2000 के अनुमानों अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 37.43 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। ग्रामीण जनसंख्या में से 37.06 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। मतलब यह है कि लगभग एक तिहाई से ज्यादा जनसंख्या गरीबी के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि योजना आयोग और भारत सरकार गरीबी को सीधे-सीधे भोजन की उपलब्धता से जोड़कर देखते हैं। गरीबी का मतलब प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहण करने से जुड़ा हुआ है।

अब हम अगर मध्यप्रदेश में गरीबी को समझना चाहे तो यह भी समझना जरूरी है कि प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहण करने की क्षमता घर या परिवार में खाद्यान्न की उपलब्धता से सीधे-सीधे जुड़ा है। अतः खाद्यान्न, खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न सुरक्षा की संरचना प्रदेश की गरीबी से सीधे सीधे जुड़ी हुयी है। मध्यप्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति में हर वर्ष बदलाव आता रहा है इसके कई कारण हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख कृषि की स्थिति है कृषि में भी सिंचाई व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश में कुल बोए गए जमीन का 27.08 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है। प्रदेश की अधिकांश खेती वर्षा आधारित है जो कि कृषि उत्पादन को वर्षा की स्थिति से जोड़ती है और अनियमित बनाती है।

e/; çns'k ea [kkk Uu , oa uxnh Ql yka dk mRi knu % ā; k yk[k efvđ Vu e#					
कृषि उत्पादन	1998-99	1900-00	2000-01	2001-02	2002-03
धान	13 <sup>०84</sup>	17 <sup>०1</sup>	9 <sup>42</sup>	16 <sup>०92</sup>	9
गेहूँ	82 <sup>०55</sup>	86 <sup>०85</sup>	84 <sup>०69</sup>	60	42 <sup>०85</sup>
ज्वार	7 <sup>०18</sup>	5 <sup>०27</sup>	4 <sup>०6</sup>	5 <sup>०8</sup>	5 <sup>०57</sup>
सभी अनाज	118 <sup>०75</sup>	125 <sup>०78</sup>	79 <sup>०1</sup>	103 <sup>०82</sup>	75 <sup>०34</sup>
सभी दालें	33 <sup>०72</sup>	34 <sup>०23</sup>	22 <sup>०75</sup>	32 <sup>०24</sup>	22 <sup>०2</sup>
कुल खाद्यान्न	152 <sup>०47</sup>	160 <sup>००1</sup>	101 <sup>०85</sup>	136 <sup>००6</sup>	97 <sup>०55</sup>
rkfydk % 2 l ksr % e/; çns'k dk vkfkkđ l o[k.k] 2003&2004 rkfydk & 2					

व्यक्तिगत सिंचाई के साधन बड़े किसानों या कुछ सीमा तक मझोले किसानों के पास ही है। स पिछले 4-5 वर्षों के दौरान सिर्फ 2003-2004 में ही वर्षा सामान्य रही है अन्यथा वर्षा एकदम अनियमित रही है। अनियमित वर्षा का प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और सारणी से स्पष्ट है। यह अनियमित खाद्यान्न उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न की उपलब्धता पर नकारात्मक असर डालती है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह प्रदेश में गरीबी को बढ़ा सकती है। क्योंकि गरीबी और भोजन के रूप में ली जा रही कैलोरी का आपस में सीधा सम्बन्ध है।

इस पूरी पृष्ठभूमि में लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी निवारण का आपस में सीधा-सीधा सम्बन्ध बनता है क्योंकि अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक से काम करेगी तो गरीब परिवार महीने में 5-7 दिन की मजदूरी उपलब्ध होने पर भी उचित मूल्य की दुकान से अपने परिवार के लिए आवंटित राशन खरीद सकेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस सम्बन्ध में दायर वाद से भ यह बात स्पष्ट होती है कि -

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीब और अति गरीब परिवारों के लिए बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाती है।
- इस व्यवस्था के अन्तर्गत गरीब परिवारों को (जिनके नाम गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सूची में दर्ज होते हैं!) रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है।
- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में से लगभग एक चौथाई परिवारों को अति गरीब परिवार माना गया है, जिन्हें अन्त्योदय अन्न योजना का हितग्राही माना गया है। इन परिवारों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता है। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत एक राशन कार्ड पर 35 किलो अनाज दिये जाने का प्रावधान है।

## 2- v/ ; ; u dh t: jr

एक्शन एड मध्यप्रदेश के 12-13 जिलों में स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर गरीब, बेसहारा और कमजोर लोगों की जिन्दगी में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें उनके संविधान प्रदत्त अधिकार दिलाने के लिए काम कर रही है। भोजन के अधिकार अभियान के लिए काम करते वक्त प्रदेश के अनेकों क्षेत्रों से भूख से हुई मौत की रिपोर्ट सामने आई और यह भी अनुभव हुआ कि खाद्यान्न की कमी की वजह से लोग भारी संख्या में पलायन करते हैं। अनुभवों के विश्लेषण से यह भी पता चला कि संक्षिप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ठीक से काम न कर पाने की वजह से लोगों की परिस्थिति और खराब हो जाती है विशेष रूप से वृद्ध, विकलांग, बेसहारा और विधवा और बच्चों की! यह वह वर्ग है जो पलायन के समय गांव में ही रह जाता है। इस पूरे संदर्भ में यह उल्लेख करना भी जरूरी होगा कि विगत दो वर्षों से देश के सर्वोच्च न्यायालय ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबन्धन और क्रियान्वयन व्यवस्था पर सीधी निगाह रखी शुरू की है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 मई 2003 के अपने आदेश में तय किया कि -

- बूढ़े, लाचार, विकलांग, बेसहारा, पुरुष व महिलाएं, गर्भवती महिलाएं व बच्चों को दूध्या पिलाने वाली माताएं।
- विधवा व वे एकल महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं है।
- 60 साल व उससे ऊपर के व्यक्ति जो बेसहारा हैं व जिनके पास आजीविका का कोई नियमित जरिया नहीं है।
- वे परिवार जिनमें कोई विकलांग व्यक्ति है।
- ऐसा परिवार जहां वृद्धावस्था, शारीरिक व मानसिक बीमारी, सामाजिक रीति-रिवाजों, विकलांग व्यक्ति की देखभाल तथा अन्य किन्हीं वजहों से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घर के बाहर कमाई के लिए जा सके।
- आदिम (क्षपउपजपअम) जनजातियां

इसे पूरे परिप्रेक्ष्य में कई सवाल उठते हैं कि –

- क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली सभी गरीब परिवारों को विशेष रूप से अति गरीब परिवारों को तय कदर पर राशन उपलब्ध करवा पा रही है।
- लोगों की खुद की खाद्यान्न सुरक्षा की क्या व्यवस्था है।
- क्या लोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संतुष्ट हैं।
- क्या पंचायतों और ग्राम सभा की भागीदारी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन बेहतर हुआ है।

इन्हीं सवालों पर विचार करते समय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक विस्तृत अध्ययन करने की जरूरत महसूस की गई है।

### 3- v/ ; ; u ds míś ;

इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं –

- ग्रामीण क्षेत्र, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझना।
- गांवों क्षेत्रों में खाद्यान्न सुरक्षा के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका को समझना।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में ग्रामीण लोगों के अनुभव, समस्याओं और सुझावों का विश्लेषण करना।

### 4- v/ ; ; u i ) fr

यह अध्ययन एकएशन एड भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय और सात सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से की गई है। इस अध्ययन को करने के लिए –

- गांवों से प्राथमिक आंकड़ों को संकलित किया गया है।
- सरकार व अन्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया गया है।
- गांवों में लोगों के अनुभवों के केस अध्ययन व गांवों में खाद्यान्न सुरक्षा और प्रबन्धन का इतिहास समझने की कोशिश की गई है।
- उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त आंकड़ों और उसकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण करके उसे विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

#### 4-1- v/ ; ; u {ks=

यह अध्ययन प्रदेश के सात जिलों के 7 विकास खण्डों में स्थित 40 ग्राम पंचायतों के कुल 54 गांवों में किया गया। यह अध्ययन मुख्य रूप से 28 उचित मूल्य की दुकानों के प्रभाव क्षेत्र के गांवों में ही किया गया। के लिए चुने गए क्षेत्र को निम्नलिखित सारणी – 2 में स्पष्ट किया गया है।

ftyk	cykkt	i p k ; r	xk	mfpr eW ; dh nplku
शिवपुरी	कोलारस	7	8	4
धार	धर्मपुरी	5	6	4
झाबुआ	पेटलावाद	5	8	4
खण्डवा	खालवा	7	9	4
सिवनी	खुरई	6	8	4
मण्डला	बिछिया	5	8	4
डिण्डोरी	बैजाग	5	7	4
कुल	7	40	54	28

rkfydk & 3

#### 4-2- xq kkRed vkadM\$

समूह चर्चा, व्यक्तिगत साक्षात्कार समय रेखा और केस अध्ययन जैसे विधियों से संकलित गुणात्मक आंकड़ों को नीचे की सारिणी में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इन गुणात्मक जानकारियों के विश्लेषण से बहुत सी महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं साथ ही अध्ययन के आंकड़ों के विश्लेषण में भी काफी आसानी होती है। गुणात्मक आंकड़े वास्तव में संख्यात्मक आंकड़ों के पीछे की कहानी करे और ज्यादा स्पष्ट करते हैं।

v/ ; ; u {ks= l sl l p u k l x f g r d j u s d s f y , m i ; k x d h x b l f o f k				
ftyk	l e g p p l z	0 ; f D r x r l k { k R c l k j	l e ; j s [ k k	d s l V M h
धार	8	10	8	1
झाबुआ	10	8	8	9
मण्डला	11	6	8	0
डिण्डोरी	7	2	8	0
शिवपुरी	8	13	8	4
सिवनी	8	1	8	3
खण्डवा	12	16	8	3
कुल	64	56	56	20
श्रोत : 2001 dh tux.kuk , oe e- ç- dk ekuo fodkl çfronu 2003				
rkfydk & 4				

#### 4-3- v/ ; ; u {ks= dk çkQkby

यह अध्ययन प्रदेश के सात जिलों में किया गया जो प्रदेश के अलग-अलग सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह तथ्य सारणी में प्रस्तुत है। अध्ययन क्षेत्र की प्रोफाइल से यह स्पष्ट होता है कि इस अध्ययन में मध्यप्रदेश के अधिकांश सांस्कृतिक विभिन्नता शामिल है। इस अध्ययन में बुंदेलखंड और बघेल खण्ड क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

o'k 2001 dh tux.kuk d s v k / k j i j f t y ' d h d y t u l d ; k e s v t k v j v t t k d h t u l d ; k , o e e k u o f o d k l ç f r o n u			
ftyk	सांस्कृतिक क्षेत्र	o'k 2001 dh tux.kuk d s v k / k j i j f t y ' d h d y t u l d ; k e s v t k v j v t t k d h t u l d ; k d k ç f r ' k r	ftys dk ekuo fodkl l p d k d
शिवपुरी	गवालियर - चम्बल	29 <sup>998</sup>	0 <sup>473</sup>
धार	मालवा	60 <sup>999</sup>	0 <sup>559</sup>
झाबुआ	मालवा	89 <sup>966</sup>	0 <sup>372</sup>
खण्डवा	निमार	40 <sup>976</sup>	0 <sup>563</sup>
सिवनी	महाकौशल	47 <sup>912</sup>	0 <sup>55</sup>
डिण्डोरी	महाकौशल	70 <sup>931</sup>	0 <sup>557</sup>
मण्डला	महाकौशल	61 <sup>985</sup>	0 <sup>578</sup>
श्रोत : 2001 dh tux.kuk , oe e- ç- dk ekuo fodkl çfronu 2003			
rkfydk & 5			

सभी सातों जिले प्रदेश के विभिन्न छोरों पर स्थित हैं जो नीचे सारणी में स्पष्ट है

ftyk	LFkku	tutkfr; ka	v/ ; ; u xkeka dh tul d ; k
शिवपुरी	पश्चिमी म. प्र., राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर	सहरिया जनजाति जो कि आदिम जनजाति घोषित है	सभी गांव सहरिया बहुल
धार	पश्चिमी मध्यप्रदेश राजस्थान की सीमा पर	भील-भिलाला जिले की कई तहसील अनुसूचित क्षेत्र	भील-भिलाला बहुल गांव
झाबुआ	पश्चिमी मध्यप्रदेश में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सीमा पर	भील-भिलाला जिले की कई तहसील अनुसूचित क्षेत्र	भील-भिलाला बहुल गांव
खण्डवा	दक्षिणी मध्यप्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लगा	भील-भिलाला जिले की कई तहसील अनुसूचित क्षेत्र	भील-भिलाला बहुल गांव
सिवनी	पूर्वी मध्यप्रदेश में महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित	गोंड व कोरकू प्रमुख जनजातियां जिले की अधिकांश तहसीलें पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित	गोंड बहुल गांव
मण्डला	म. प्र. के पूर्वी छोर पर छत्तीसगढ़ की सीमा पर	गोंड व बैगा पूरा जिला अनुसूचित क्षेत्र बैगा आदिम जनजाति	गोंड बहुल गांव
डिण्डोरी	पूर्वी म. प्र.	गोंड व बैगा पूरा जिला अनुसूचित क्षेत्र बैगा आदिम जनजाति	बैगा बहुल गांव
rkfydk & 10			

#### 4-4- xkoka dh ckQkbly

गांवों में सुविधाओं की स्थिति और उचित मूल्य के दुकान की स्थिति नीचे सारिणी में दी गई है—

Øe l f; k	xko ea foF"Uu l fo/kv'a dh fLFkr										
	dly xte" dh l f; k	l Md l s tMf xko'a	Ldy dh l fo/kk	ih, p- l h	mfpr eW; dh ntku	xko dk cktkj	j'LV vFOI	Q' dh l fo/kk	cdt	foj kus dh ntku	vkoUMH
1 शिवपुरी	8	2	7	0	1	0	0	1	0	0	7
2 धार	8	3	7	0	3	0	0	2	0	3	7
3 झाबुआ	8	1	8	0	2	0	0	0	0	0	8
4 खण्डवा	9	3	9	3	4	2	3	4	1	1	9
5 मण्डला	8	1	6	0	1	0	1	1	0	0	5
6 डिण्डौरी	8	4	3	1	3	1	1	0	1	1	8
7 सिवनी	8	2	4	0	2	0	2	0	0	4	7
Dy	57	16	44	4	16	3	7	8	2	9	51
J'r%v/; ; u ds vkmf; dk fo'yšk.k											
rkfydk & 11											

28 प्रतिशत गांवों में उचित मूल्य की दुकान है और 72 प्रतिशत गांवों के लोगों को राशन के लिए गांव से बाहर स्थित उचित मूल्य की दुकान पर जाना पड़ता है।

#### 4-5- v/; ; u ea 'kkfey xkeh.kka ds fy, ntku dh njh

अध्ययन में 7 जिलों के कुल 7970 व्यक्तियों से बातचीत की गई। इन लोगों के हिसाब से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों के लिए दुकान कहां पर स्थित है। यह सारिणी में प्रस्तुत है।

इस सारणी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि 32.4 प्रतिशत लोगों के गांव में ही राशन की दुकान है जबकि लगभग 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को राशन के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। लगभग 23.1 प्रतिशत उत्तर दाता अपने गांव से 3 से 6 किमी दूर जाते हैं तो 7.4 प्रतिशत उत्तरदाता 6-9 किमी दूर जाते हैं।

xko l smfpr eW; ds ntku dh nejh							
ftyk	xko ea gji	xko l s 1 l s 3 fdeh: nj	xko l s 3 l s 6 fdeh: nj	xko l s 6 l s 9 fdeh: nj	9 l T: krk	Tok ugha	dly
धार	105	137	37	0	0	1	280
	37%5	48%9	13%2	0	0	0%4	100
डिण्डौरी	80	140	47	0	0	2	269
	29%7	52%0	17%5	0	0	0%7	100
झाबुआ	63	138	88	1	0	4	294
	21%4	46%9	29%9	0%3	0	1%4	100
खण्डवा	212	51	20	3	0	4	290
	73%1	17%6	6%9	1%0	0	1%4	100
मंडला	35	100	106	35	2	1	279
	12%5	35%8	38%0	12%5	0%7	0%4	100
सिवनी	108	99	70	1	0	0	278
	38%8	35%6	25%2	0%4	0%0	0%0	100
शिवपुरी	35	51	88	105	0	1	280
	12%5	18%2	31%4	37%5	0%0	0%4	100
कुल	638	716	456	145	2	13	1970
	32%4	36%3	23%1	7%4	0%1	0%7	100
J'r%v/; ; u ds vkmf; dk fo'yšk.k							

#### 4-6- mÜkj nkrkvka dk çkQkbly

किस जिले के कितने उत्तरदाता किस वर्ग के कार्ड धारक हैं यह नीचे सारणी में स्पष्ट किया गया है।

सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 57 प्रतिशत उत्तरदाता गरीबी रेखा के नीचे वाले वर्ग से हैं। अन्त्योदय वर्ग से 29.3 प्रतिशत उत्तरदाता हैं और 13.7 प्रतिशत उत्तरदाता गरीबी रेखा से ऊपर वाले वर्ग के कार्ड धारक हैं। लगभग 87.6 प्रतिशत उत्तर पुरुष हैं और 12.4 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएं हैं। अधिकांश उत्तरदाता (लगभग 38 प्रतिशत) 31 से 40 वर्ष की उम्र श्रेणी के हैं। 41 से 50 वर्ष की बीच की उम्र वाले उत्तरदाता 24.9 प्रतिशत हैं और 17.2 प्रतिशत उत्तरदाता 21 से 30 वर्ष के उम्र के बीच के हैं।

DkMZ /kkj dka dh Js kh				
ftys	vR; n; Js kh ds dkMZ /kkj d	xjhch js'kk Js kh ds dkMZ /kkj d	xjhch js'kk l s Äij dh Js kh ds dkMZ /kkj d	dgy
शिवपुरी	93 ,33%:द	96 ,34%:द	89 ,32:द	278
झाबुआ	80 ,27%:द	213 ,72%:द	1 ,0%:द	294
धार	80 ,28%:द	160 ,57%:द	40 ,14%:द	280
खण्डवा	79 ,27%:द	165 ,57%:द	42 ,14%:द	286
सिवनी	78 ,28%:द	161 ,57%:द	39 ,14:द	278
मंडला	99 ,35%:द	164 ,58%:द	16 ,5%:द	279
डिण्डोरी	66 ,24%:द	161 ,59%:द	42 ,15%:द	269
कुल	575 ,29%:द	1120 ,57:द	269 ,13%:द	1964
श्रोत: अध्ययन के आँड़ो का विश्लेषण				

#### 4-7- ftyka ea xjhch vkj vl; rF;

अध्ययन के लिए चुने गए जिलों में ग्रामीण गरीबी, और अनुसूचित जाति तथा जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत नीचे दिया गया है। सारणी के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि मण्डला, डिण्डोरी और झाबुआ सर्वाधिक गरीब जिलों में आते हैं और साथ ही इन जिलों में अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी का अनुपात भी काफी ज्यादा है। झाबुआ का मानव विकास सूचकांक भी अत्यन्त कम है।

ftys	ftys ds xkeh.k {k- ea xjhch js'kk l s ulps thou ;kiu djus okys i fjokjka dk i fr'kr	ftys dh tul d; k ea vuq l i pr tkfr , oa tutkr ds i fjokjka dk l ; qR i fr'kr	ftys dk ekuo fodkl l pdkad
f'koijh	29%62	29%98	0%473
/kkj	38%76	60%99	0%559
fl ouh	41%4	47%42	0%55
[k. Mok	44%83	40%76	0%563
>kcmk	54%37	89%66	0%372
fM. Mkjh	57%09	70%31	0%557
eMyk	59%08	61%85	0%578
श्रोत : 2001 dh tux.kuk ,oe e- ç- dk ekuo fodkl çronu 2003			

#### 5- Hkkjr o"kl ea l f{klr l ko'ftud forj.k iz.kkylh

हमने यह समझने का प्रयास किया कि समान पृष्ठभूमि वाले राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति क्या है। परिस्थितियों की तुलना के लिए हमने आन्ध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा उत्तरप्रदेश, और राजस्थान को चुना है। इनमें से उत्तरप्रदेश और राजस्थान पड़ोसी राज्य हैं। छत्तीसगढ़ 31 अक्टूबर 2000 तक मध्यप्रदेश में शामिल था और इसी समय तक आंध्रप्रदेश, बिहार और उड़ीसा मध्यप्रदेश के पड़ोसी राज्य थे।

##### 5-1- xjhch

वर्ष 1972-73 में मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़ शामिल) उड़ीसा और बिहार में 60 प्रतिशत से ज्यादा गरीबी थी जबकि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में गरीबी 40 से 50 प्रतिशत के बीच में थी। वर्ष 1999-2000 में आंध्रप्रदेश और राजस्थान में यह गरीबी रेखा 15 प्रतिशत से नीचे आ गई जबकि बिहार और उड़ीसा में यह अभी भी 40 से 50 प्रतिशत के बीच में बनी हुई है। मध्यप्रदेश में गरीबी 37.43 प्रतिशत है जो 40 के बहुत नीचे नहीं है।

xkeh.k xjhch js[kk ds vuq kr ea i fjo rL						
jkt;	1973-74	1977-78	1983	1987-88	1993-94	1999-00
बिहार	62 <sup>99</sup>	63 <sup>25</sup>	64 <sup>37</sup>	52 <sup>63</sup>	58 <sup>21</sup>	44 <sup>93</sup>
मध्यप्रदेश	62 <sup>66</sup>	62 <sup>52</sup>	48 <sup>99</sup>	41 <sup>92</sup>	40 <sup>64</sup>	37 <sup>06</sup>
उड़ीसा	67 <sup>28</sup>	72 <sup>38</sup>	67 <sup>53</sup>	57 <sup>64</sup>	49 <sup>72</sup>	48 <sup>01</sup>
उत्तरप्रदेश	56 <sup>53</sup>	47 <sup>96</sup>	46 <sup>45</sup>	41 <sup>91</sup>	42 <sup>28</sup>	31 <sup>22</sup>
आन्ध्रप्रदेश	48 <sup>41</sup>	38 <sup>11</sup>	26 <sup>53</sup>	20 <sup>92</sup>	15 <sup>92</sup>	11 <sup>05</sup>
राजस्थान	44 <sup>76</sup>	35 <sup>89</sup>	33 <sup>95</sup>	33 <sup>21</sup>	26 <sup>46</sup>	13 <sup>74</sup>
I Eiwk "kjr	56.44	53.07	45.65	39.09	37.27	27.09
Hkkjr dk ; kstuk vk; ksx fu; kst u dh l f[; dh; i kOkby 1999&90 Hkkjr l jckj rkyfck & 6						

## 5-2- I ko'tfud forj.k ç.kkyh ea fgrxkfg; ka dh Jf.k; ka

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्रहियों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है, यह श्रेणियां नीचे स्पष्ट की गई हैं।

### 5-2-1- vUR; kn; vlu ; kstuk ds vfr xjhc

भारत सरकार ने जनवरी 2001 से यह योजना शुरू की। हर प्रदेश के कुल गरीबों के 25 प्रतिशत भाग को अति गरीब माना गया है। अति गरीब परिवारों की राज्यवार सारणी इस प्रकार है –

fof"lu çns'ka ea vR; "n; i fjokj" dh fLFkr				
Ø-	jkt;	vR; "n; ; kstuk ds vllrxr çLrkfor i fjokj ka dh l f[; k %yk[k ea	jkt; l jckj }jkj vR; "n; ; kstuk ds vllrxr igpku fd, x, vkj jk'ku dkMZ forfjr fd, i fjokj ka dh l f[; k %yk[k ea	vR; "n; ; kstuk ds vllrxr jk'ku dkMZ çkr fd, i fjokj ka dh çfr'kr
1	आंध्रप्रदेश	12 <sup>336</sup>	12 <sup>336</sup>	100 <sup>90</sup>
4	बिहार	19 <sup>805</sup>	10 <sup>000</sup>	50 <sup>95</sup>
5	छत्तीसगढ़	5 <sup>989</sup>	4 <sup>619</sup>	81 <sup>91</sup>
15	मध्यप्रदेश	12 <sup>525</sup>	9 <sup>488</sup>	75 <sup>98</sup>
21	उड़ीसा	10 <sup>013</sup>	5 <sup>055</sup>	50 <sup>95</sup>
23	राजस्थान	7 <sup>381</sup>	5 <sup>733</sup>	77 <sup>97</sup>
28	उत्तरप्रदेश	32 <sup>423</sup>	32 <sup>423</sup>	100 <sup>90</sup>
तालिका – सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्रोत : भारत सरकार की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की विभागीय वेब साइटरू rkyfck & 7				

इस सारणी से यह स्पष्ट होता है कि सिर्फ आंध्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश ने ही सभी अन्तयोदय परिवारों की पहचान और कार्ड वितरण का का शत-प्रतिशत पूरा किया है। मध्यप्रदेश अभी भी लगभग 25 प्रतिशत अन्तयोदय परिवारों को अति गरीब के रूप में पहचान हो जाने के बाद कार्ड उपलब्ध नहीं करा पाया है।

### 5-2-2- xjhch js[kk ds uhps okys i fjokj

वर्तमान में सभी प्रदेशों द्वारा वर्ष 1997-98 में पहचाने गये गरीब परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे का परिवार मानकर उन्हें सस्ते दर पर राशन दिया जा रहा है। अप्रैल 2002 से हर परिवार (अन्तयोदय, गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर के परिवार) को प्रति माह 35 किलो के हिसाब से राशन की पात्रता तय की गई है।

### 5-2-3- xjhch js[kk ds Åij okys i fjokj

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के अलावा गांव के सभी परिवार इस श्रेणी में आते हैं। अध्ययन में तुलना के लिए लिए राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत तय कीमतों नीचे सारिणी में स्पष्ट की गई हैं।

I Hkh Jf.k; ka ea l koİtfud forj.k ç. kkyh ds fy, dgy [kk   kUka dk vkoà/u , oa mBko				
jkt;	chi h, y		, ih, y	
	xg	pkoy	xg	pkoy xM ,
आन्ध्रप्रदेश <sup>1</sup>	7900	5925	7900	9900
बिहार	4973	6922	6980	9922
छत्तीसगढ़	4965	6915	6981	9904
मध्यप्रदेश <sup>2</sup>	5900	6950	7900	9920
उड़ीसा	4990	6930	7900	9930
राजस्थान	4960	6915	6965	8995
उत्तर प्रदेश	4965	6915	6960	8945
केन्द्र द्वारा निर्धारित मूल्य	4915	5965	-	-
तालिका - सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्रोत : भारत सरकार की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की विभागीय वेब साइट rkfydk & 8				

### 6- jkT; ka dks [kk | kUu dk vkoà/u , oa mBko

वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न और राज्यों द्वारा उनके उठाव के आंकड़ें नीचे दिए गए हैं -

I Hkh Jf.k; ka ea l koİtfud forj.k ç. kkyh ds fy, dgy [kk   kUka dk vkoà/u , oa mBko									
jkt;	vR; n;			xjhch js[kk ds i fjokj			xjhch js[kk ds mi j ds i fjokj		
	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
o"z	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
Fcgkj	60 ,729087द	168 ,77918द	252 ,91976द	656937 ,9885द	9029712 ,69372द	8879712 ,696द	689732 ,0988द	91695572 ,09662द	13749848 ,0946द
e/; çns k	57912 ,9099द	689737 ,9894द	549113 ,949292द	2899756 ,41995द	3299751 ,50966द	2049946 ,819199द	649188 ,1923द	8419679 ,0914द	4649816 ,09217द
mVhl k	869466 ,989656द	2129316 ,859579द	0 ,0द	9079045 ,539821द	14849376 ,249390द	14849376 ,429637द	44964 ,25995द	10159098 ,09005द	7959564 ,09901द
NUkl x<+	86922 ,9093द	120971 ,3986द	153996 ,94द	305978 ,4895द	4509576 ,29322द	4459936 ,919458द	609012 ,0935द	620977 ,0द	62097 ,09216द
mUkj çns k	829111 ,102931द	230924 ,9696द	2849873 ,10895द	7369649 ,34944द	12419032 ,4098द	12529893 ,50996द	1269636 ,0974द	26319528 ,09114द	4314984 ,09225द
vkl/çns k	186984 ,102951द	2619576 ,8997द	3379946 ,97984द	1470996 ,6691द	144498 ,99976द	1368943 ,969405द	1495968 ,37972द	21139068 ,1692द	21139068 ,19984द
jkT LFku	19284 ,379द	198 ,2098द	29092 ,1792द	69282 ,594द	9925 ,4935द	8996 ,391द	9936 ,197द	72921 ,09069द	26969376 ,4912द
Hkj r	196091 ,85962द	4127953 ,8597द	4555991 ,9194द	1786692 ,56927द	22771912 ,5993द	22549921 ,7091द	10545933 ,19997द	47784965 ,694द	44459779 ,99502द
rkfydk & 9									

प्रस्तुत आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि अन्त्योदय श्रेणी में खाद्यान्न के उठाव का प्रतिशत काफी अच्छा है। और मध्यप्रदेश द्वारा उठाव य90 प्रतिशत से ज्यादा का रहा है। आवंटन की स्थिति यह स्पष्ट करती है कि राज्यों को किया जाने वाला आवंटन किसी सिद्धांत के आधार पर न होकर राज्य का केन्द्र के ऊपर प्रभाव के आधार पर तय होता है। आंध्रप्रदेश, जिसकी जनसंख्या मध्यप्रदेश से कम है, जहां गरीबी का प्रतिशत कम है वहां पर हर श्रेणी में अनाज का आवंटन मध्यप्रदेश या किसी भी दूसरे, राज्य (चुने गए राज्यों) से ज्यादा है।

### 6-1- ftyka ea vkoà/u , oa mBko

अध्ययन के सातों जिलों में गेहूँ और चावल के गरीबी रेखा के लिए आवंटन तथा उठाव को नीचे दो सारणियों में स्पष्ट किया गया है -

<sup>1</sup> अतिरिक्त सस्मिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी

<sup>2</sup> अलग-अलग क्षेत्रों में बदलता है

xjhch jskk ds ifjokjka ea forj.k ds fy, ftyks dks xgg dk vko/u , oa mBko						
ftys	Xjhch jskk %vko/u Vu ea %			Xjhch jskk % ftyka jkjk mBkok dk ifr'kr %		
	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
f'ki ojh	7200	18540	6672	122 <sup>01</sup>	81 <sup>02</sup>	168 <sup>05</sup>
/kkj	30240	53016	58620	93 <sup>02</sup>	58 <sup>05</sup>	68 <sup>09</sup>
fl ouh	10800	14448	23436	63 <sup>00</sup>	56 <sup>07</sup>	48 <sup>00</sup>
[kMok	13308	30588	37692	113 <sup>07</sup>	73 <sup>03</sup>	78 <sup>03</sup>
>kcq/k	26112	27120	39288	70 <sup>04</sup>	95 <sup>00</sup>	84 <sup>05</sup>
fM. Mjsh	3600	5652	10140	33 <sup>08</sup>	27 <sup>05</sup>	3 <sup>03</sup>
emyk	4692	6228	17292	69 <sup>09</sup>	51 <sup>01</sup>	19 <sup>09</sup>
सेत्र : मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से दिसंबर 2004 में एकत्र किए गये आंकड़ों के आधार पर						

xjhch jskk ds ifjokjka ea forj.k ds fy, ftyks dks pkoy dk vko/u , oa mBko						
Ftys	Xjhch jskk %vko/u Vu ea %			Xjhch jskk % ftyka jkjk mBkok dk ifr'kr %		
	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
f'ki ojh	1920	2400	1152	78 <sup>06</sup>	67 <sup>08</sup>	68 <sup>06</sup>
/kkj	816	3264	1308	59 <sup>09</sup>	36 <sup>00</sup>	84 <sup>00</sup>
Fl ouh	10104	10716	5976	45 <sup>08</sup>	56 <sup>09</sup>	111 <sup>03</sup>
[kMok	5076	12960	8904	120 <sup>03</sup>	67 <sup>01</sup>	94 <sup>01</sup>
>kcq/k	7200	5544	4356	80 <sup>02</sup>	97 <sup>02</sup>	85 <sup>04</sup>
fM. Mjsh	9576	9780	9972	39 <sup>05</sup>	39 <sup>00</sup>	35 <sup>01</sup>
emyk	14400	19044	8196	45 <sup>06</sup>	32 <sup>07</sup>	68 <sup>05</sup>
सेत्र : मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से दिसंबर 2004 में एकत्र किए गये आंकड़ों के आधार पर						

आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2001-2002 में शिवपुरी तथा खण्डवा में गेहूं का उठाव 100 प्रतिशत से ज्यादा है। वर्ष 2003-04 में शिवपुरी में गेहूं का उठाव 168.5 प्रतिशत है। शेष जिलों में उठाव 100 प्रतिशत से कम है और शिवपुरी को छोड़कर हर जिलों में यह उठाव 2001-02 की स्थिति से भी कम है। मण्डला, डिण्डौरी में उठाव की स्थिति अत्यन्त खराब है। चावल के आवंटन तथा उठाव के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि वर्ष 2001-2002 में खण्डवा में 120 प्रतिशत उठाव था तो वर्ष 2003-04 में सिवनी में 111.3 प्रतिशत चावल उठाया था। डिण्डौरी के द्वारा उठाए गए चावल का प्रतिशत 40 से भी कम है। आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि सभी गरीब परिवारों को राशन नहीं मिल सकता या कम राशन मिल रहा है।

## 7- y{; vk/kkfjr l ko'fud forj.k iz.kkjh ij Hkkjr dk l okPp U; k; y;

### 7-1- fnukd % 28-11-2001

#### 1. लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)

1. भारतीय संघ का कहना है कि टीपीडीएस के संदर्भ में खाद्यान्न के आवंटन के मामले में पूर्ण अनुपालन हुआ है। फिर भी यदि कोई राज्य पूर्ण अनुपालन न होने की किसी विशेष घटना को प्रकाश में लाता है तो इस कार्यक्रम के दायरे में भारतीय संघ आवश्यक कार्रवाई करेगा।
2. राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे 1 जनवरी 2002 तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की शिनाख्त पूरी कर लें, राशन कार्ड जारी कर दें और प्रतिमाह परिवार 25 किलो खाद्यान्न का वितरण आरम्भ कर दें।
3. दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टीपीडीएस के आवेदन फार्म आसानी से उपलब्ध हैं तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। दिल्ली सरकार शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए एक प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।

#### 2- vUr; kn; vUu ; kstuk

1. भारतीय संघ कहना है कि अन्त्योदय अन्न योजना के लिए खाद्यान्न के आवंटन के मामले में पूर्ण अनुपालन हुआ है। परन्तु यदि कोई राज्य पूर्ण अनुपालन न होने की

स्थिति में कोई विशेष घटना प्रकाश में लाता है तो इस स्कीम के दायरे में भारतीय संघ आवश्यक कार्रवाई करेगा।

2. हम राज्यों को और संघ शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि वे 1 जनवरी 2002 तक इस स्कीम के तहत लाभार्थियों की शिनाख्त, कार्ड जारी करने और अनाज के वितरण का काम पूरा कर दें।
3. यह प्रतीत होता है कि अन्त्योदय लाभार्थी अति निर्धनता के कारण अनाज उठाने में असमर्थ हो सकते हैं। ऐसे मामलों में केन्द्र, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे अपनी पूर्ण संतुष्टि के बाद अनाज का कोटा निःशुल्क देने पर विचार करें।

## 7-2- fnukad 8 ebl 2002

(क) प्रतिवादीगण सुनिश्चित करेंगे कि राशन दुकानें पूरे महीने निश्चित घंटे में खुली रहेंगी, इसका ब्यौरा सूचना पट्टा पर प्रदर्शित किया जायेगा।

## 7-3- fnukad 29-10-2002

- अगर अब न्यायालय के आदेशों को मनवाने में हीला-हवाली की गई तो इसके लिए राज्यों के मुख्य सचिव और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जिम्मेदार होंगे।
- मुख्य सचिवों या प्रशासकों को यह आखिरी मौका है कि वे न्यायालय के 28 नवम्बर 2001 तथा 8 मई 2002 के आदेशों को अनुवादित कराकर प्रमुखता के साथ उनका सभी ग्राम पंचायतों, स्कूलों, भवनों तथा राशन की दुकानों पर स्थाई तरीकों से प्रदर्शन करें। रेडियो और दूरदर्शन से भी उनका खूब प्रचार कराया जाए। यह काम आठ सप्ताह के भीतर हो जाना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की ड्यूटी है कि वे भूख, कुपोषण से होने वाली मौतों की रोकथाम करें। अगर कमिश्नर ऐसी कोई रिपोर्ट देता है और न्यायालय को भी लगता है कि वाकई में कोई भूख से मरा है तो माना जायेगा कि आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तथा इसके लिए राज्यों के मुख्य सचिव तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा।

## 7-4- fnukad 2 ebl 2003

इस कोर्ट (भारत का सर्वोच्च न्यायालय) ने पिछले दो वर्षों में भी अपने विभिन्न आदेशों में इस मामले पर गहरी चिंता जाहिर की है। एक आदेश में कोर्ट ने यह कहा है कि बूढ़े, लाचार व्यक्तियों, विकलांगों, बेसहारा महिलाओं व बूढ़े पुरुषों जो कि भुखमरी के कगार पर हों, गर्भवती महिलाओं व बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं तथा बेसहारा बच्चों को भोजन उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। खासकर उन मामलों में जहां उनके पास या उनके परिवार के पास इतना भोजन उपलब्ध नहीं है कि उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सके। अकाल के समय में खाने की कमी हो सकती है, लेकिन यहां वास्तविक स्थिति यह है कि काफी मात्रा में भोजन है परन्तु उसका वितरण बहुत गरीब व बेसहारा लोगों के मामलों में या तो बहुत कम है या बिल्कुल न के बराबर है, जिसकी वजह से कुपोषण, गरीबी व इनसे जुड़ी दूसरी समस्याएं पैदा हो रही हैं। कोर्ट की मुख्य चिंता यह है कि समाज का कमजोर तबका भूख या भुखमरी से त्रस्त न हों। लोगों को भूख से बचाना केन्द्र व राज्य सरकार दोनों की मुख्य जिम्मेदारी है। केवल योजनाएं बना देना जिनका क्रियान्वयन न हो किसी काम का नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भोजन भूखे तक पहुंचे।

संविधान के अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को "मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार" दिया गया है क्या वे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, अपने जीने के लिए सही किस्म की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के अभाव में संविधान में दिये गये इस अधिकार से वंचित नहीं हैं? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हें जरूरी मदद दी जाए ताकि ये जी सकें। इसी संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 47 का हवाला भी दिया जा सकता है जिसमें यह कहा गया है कि अपने नागरिकों के पोषण

स्तर को ऊंचा उठाना, उनके जीवन स्तर को बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी होगी। हम याद दिलाना चाहेंगे कि पिछले साल मई में यह आदेश दिया गया था कि राशन की दुकानें पूरे महीने कुछ निर्धारित घंटों के दौरान खुलें व इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर जन सामान्य को दी जाए।

अनाज के वितरण के लिए हम (सर्वोच्च न्यायालय) निम्न निर्देश दें रहे हैं –

1. राशन की दुकानों के वे संचालनकर्ता –
  - A. जो अपनी दुकानें पूरे माह निर्धारित समय तक न खोलते हों।
  - B. गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को उनके लिए निर्धारित दरों पर अनाज उपलब्ध न करवाते हों,
  - C. बीपीएल परिवारों के कार्ड अपने पास रखते हों
  - D. बीपीएल कार्ड में गलत सूचनाएं भरते हों।
  - E. राशन के अनाज के खुले बाजार में बेंचते हों या उन व्यक्तियों को बेच देते हों जो बीपीएल सूची के बाहर हों और राशन की दुकानें व्यक्तियों/संस्थाओं को चलाने के लिए देते हों,
  - F. उनका लाइसेंस, तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाना चाहिए। सम्बन्धित अधिकारी इस संबंध में कोई ढिलाई नहीं देंगे।
2. गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को अपने हिस्से का अनाज किशतों में खरीदने की अनुमति होगी।
3. इस आदेश को बड़े स्तर पर प्रसारित किया जाए, ताकि बीपीएल परिवार 'अनाज' के अपने अधिकार के बारे में जान सकें।

23 जुलाई 2001 के आदेश में गरीब, लाचार विकलांग व्यक्तियों के लिए भोजन उपलब्ध करवाने के बारे में जो कहा गया था उसे भी यहां लिखा जा रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ व्यक्ति अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड के हकदार हैं भारत सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों को भी अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल करें।

1. बूढ़े, लाचार, विकलांग, बेसहारा, पुरुष व महिलाएं, गर्भवती महिलाएं व बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं।
2. विधवा व वे एकल महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं है।
3. 60 साल व उससे ऊपर के व्यक्ति जो बेसहारा हैं व जिनके पास आजीविका का कोई नियमित जरिया नहीं है।
4. वे परिवार जिनमें कोई विकलांग व्यक्ति है।
5. ऐसा परिवार जहां वृद्धावस्था, शारीरिक व मानसिक बीमारी, सामाजिक रीति-रिवाजों, विकलांग व्यक्ति की देखभाल तथा अन्य किन्हीं वजहों से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घर के बाहर कमाई के लिए जा सके।
6. आदिम जनजातियां

इनके अलावा ऊपर हमने बीपीएल कार्ड धारकों को अनाज की प्रभावी वितरण के संदर्भ में जो बातें कहीं वे सभी उन पर लागू होंगी जो अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल हैं।

## 7-5- vkns kka ds fufgrkFKZ

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ एवं अन्य के संदर्भ में रू याचिका (सी) नं. 2001 की 196, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि गरीब लोग दरिद्रजन तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोग भूख व भुखमरी से पीड़ित न हो। भूख और भुखमरी रोकना केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों की सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी है। भूख और भुखमरी दोनों का उल्लेख कर सर्वोच्च न्यायालय ने

तत्कालिक और दीर्घकालीन दोनों तरह की व्यवस्था को बनाने और मजबूत करने पर जोर दिया है। सर्वोच्च न्यायलय के वर्ष 2002 में दिए गए आदेशों से स्पष्ट होना है कि –

- भारतीय संघ के लिए जरूरी है कि वह सभी गरीब परिवारों को कार्ड और राशन उपलब्ध करवाएं
- राज्यों में इसका अनुपालन न होने की दशा में भारतीय संघ आवश्यक कार्यवाही करें
- अंत्योदय योजना के हितग्राहियों की पहचान करके जनवरी 2002 तक कार्ड वितरण व राशन वितरण सुनिश्चित करवाएं
- उचित मूल्य की दुकान पूरे महीने निश्चित समयावधि के लिए खुले
- सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों का स्थानीय भाषा में अनुवाद कराकर ग्राम पंचायत, स्कूलों, भवनों व राशन की दुकान पर ठीक ढंग से प्रदर्शन करे
- भूख से होने वाली मौतों को रोके अन्यथा संबंधित राज्यों के प्रमुख सचिव की जिम्मेदार माना जाए
- अगर ऐसा लगता है कि अंत्योदय के अति गरीब परिवार अपनी खराब आर्थिक परिस्थिति की वजह से अनाज खरीदने में असमर्थ है तो ऐसे मामलों में केन्द्र और राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे अपनी पूर्ण संतुष्टि के बाद अनाज का निःशुल्क कोटा देने पर विचार करें
- योजनाएं बनाने के साथ-साथ उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना भी बहुत जरूरी है

न्यायलय ने वर्ष 2003 में यह पूछा है कि जो परिवार अपनी खराब आर्थिक स्थिति की वजह से गरीबी के नीचे जी रहे हैं क्या वहाँ संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित "मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार" का उल्लंघन नहीं हो रहा ? इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायलय ने अपने पहले के दिए गए आदेशों के क्रियान्वयन में सख्ती लाने के निर्देश के साथ आदेशों की अवहेलना करना वाले दुकानदारों का लायसेंस रद्द करने के निर्देश भी दिए साथ ही में 23 जुलाई 2001 के आदेश में वर्णित गरीब व्यक्तियों को आवश्यक रूप से अंत्योदय योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। संक्षेप में कहें तो सर्वोच्च न्यायलय भारतीय संघ से यह अपेक्षा कर रहा है कि वे संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को अपनी नीतियों के निर्माण और योजना क्रियान्वयन का आधार बनाएँ।

## 8- [kk | ké % mi yC/krk ds l kr , oa t: jr dk l e;

लोगों से की गई बातचीत के आधार पर उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई संख्यात्मक और गुणात्मक जानकारी के आधार पर हमने यह पाया कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न का संकट है। चूंकि मध्यप्रदेश का अधिकांश क्षेत्र खेती के लिए वर्षा पर आधारित है। अतः पिछले कई वर्षों से हो रही कम वर्षा और सूखे ने इस संकट को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। गांव के लोगों को हम निम्न श्रेणियों के आधार पर बांट उपलब्धता एवं जरूरत का विश्लेषण करेंगे –

सम्पत्ति के आधार	श्रेणी – ८	श्रेणी – ८	श्रेणी – ८	श्रेणी – ८	श्रेणी – ८
	बड़े किसान	मध्यम श्रेणी के किसान	लघु एवं सीमान्त कृषक	ग्रामीण पारम्परिक कारीगर	भूमिहीन मजदूर
निर्भरता	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अपने खेतों के उत्पादन पर</li> <li>● गांव के बाहर व्यवसाय या आमदनी के दूसरे मजबूत स्रोत</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अपने खेतों का उत्पादन</li> <li>● अनाज के खरीद बिक्री का काम</li> <li>● परिवार के कुछ सदस्य सरकारी या प्राइवेट नोकरी में</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अपनी जमीन से 3-6 महीने की जरूरत पूरी</li> <li>● कृषि श्रमिक के रूप में काम</li> <li>● निर्माण क्षेत्र में भी श्रमिक के रूप में काम</li> <li>● कुछ परिवारों द्वारा खेतिहर मजदूर के रूप पलायन</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जमीन के छोटे टुकड़े जिनसे कभी कुछ अनाज मिल जाता है कभी नहीं।</li> <li>● अपने पारम्परिक उत्पाद की मांग कम या खत्म</li> <li>● हमें परिवार पलायन भी करते हैं।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● खेतिहर मजदूरी से 2-3 महीने का खाद्यान्न</li> <li>● हर तरह की मजदूरी</li> <li>● पलायन से भी 3-4 महीने का खाद्यान्न</li> </ul>

आंकड़ों से यह पता चलता है कि लोगों की खाद्यान्न की जरूरत निम्न स्रोतों से पूरी होती है –

- खुद का उत्पादन
- मजदूरी का अनाज
- मजदूरी में मिले रूपयों से अनाज की खरीदी निम्न स्रोतों से।
  - उचित मूल्य की दुकान

- खुले बाजार से
- गांव के बड़े किसानों या साहूकारों से कर्ज पर अनाज लेना

[kkn; ku dh t: jr ijk ghus ds Jks=						
ftys	vi uk mki knu	[kays cktkj l s	m/kkj	ni j s Jkka l s 0; oLFkk	dkbz 0; oLFkk ugha	dy
धार	114	115	41	5	5	280
:	11 <sup>46</sup>	28 <sup>89</sup>	14 <sup>59</sup>	2 <sup>12</sup>	8 <sup>33</sup>	
डिण्डौरी	254	2	6	1	6	269
:	25 <sup>53</sup>	0 <sup>50</sup>	2 <sup>14</sup>	0 <sup>42</sup>	10 <sup>00</sup>	
झाबुआ	263	15	9	6	1	294
:	26 <sup>43</sup>	3 <sup>77</sup>	3 <sup>20</sup>	2 <sup>54</sup>	1 <sup>67</sup>	
खण्डवा	63	111	13	73	30	290
:	6 <sup>33</sup>	27 <sup>89</sup>	4 <sup>63</sup>	30 <sup>93</sup>	50 <sup>00</sup>	
मंडला	142	8	23	104	2	279
:	14 <sup>27</sup>	2 <sup>01</sup>	8 <sup>19</sup>	44 <sup>07</sup>	3 <sup>33</sup>	
सिवनी	75	53	92	43	15	278
:	7 <sup>54</sup>	13 <sup>32</sup>	32 <sup>74</sup>	18 <sup>22</sup>	25 <sup>00</sup>	
शिवपुरी	84	94	97	4	1	280
:	8 <sup>44</sup>	23 <sup>62</sup>	34 <sup>52</sup>	1 <sup>69</sup>	1 <sup>67</sup>	
कुल	995	398	281	236	60	1970
:	50 <sup>5</sup>	20 <sup>2</sup>	14 <sup>3</sup>	12 <sup>0</sup>	3 <sup>0</sup>	

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

लोगों के अपने उत्पादन से कुल जरूरत का अधिकतम 30 से 40 प्रतिशत अनाज ही मिल पाता है और शेष की आपूर्ति बाहर से करनी पड़ती है। लगभग 48 प्रतिशत उत्तरदाता यह बता रहे हैं कि उनकी खाद्यान्न की अधिकांश जरूरत अपने उत्पादन से न होकर दूसरे स्रोतों पर टिकी है। 50.5 प्रतिशत उत्तरदाता अनाज के लिए अपने उत्पादन पर निर्भर तो है लेकिन उन्हें भी दूसरे स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है।

### 8-1- [kk | klu dh ekfl d t: jr

खाद्यान्न की जरूरत का विश्लेषण करते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि लोगों के लिए सिर्फ गेहूं और चावल ही खाद्यान्न नहीं है। अपितु वे बहुत सारे दूसरे अनाज गेहूं चावल की तुलना में ज्यादा पसन्द करते हैं। उदाहरण के तौर पर झाबुआ में मक्का का प्रचलन काफी है। सिवनी, खण्डवा, और धार में भी मक्का खाया व पसन्द किया जाता है। इसी प्रकार मण्डला व डिण्डौरी में साव, कुटकी व कोंदों जैसे स्थानीय परम्परागत अनाज काफी पसन्द किए जाते हैं। जिले वार गेहूं व चावल की जरूरत (जन्त्योदय परिवार) नीचे सारिणी में दी गई है।

vī; kn; ifjokjka dh ploy dh ekfl d t: jr							vī; kn; ifjokjka dh xgn dh ekfl d t: jr							
ftys	ekfl d t: jr vīdyks xke eñ						dy mRrjnkrk vka l d; k	ftys	ekfl d t: jr vīdyks xke eñ					
	1-5	5-15	16-25	dg l d; k ugha	tok C ugha	1-5			5-15	16-25	26-35	36-54	tok C ugha	
धार	18	11	0	0	42	80	धार	0	0	0	80	0	0	
डिण्डौरी	0	55	11	0	0	66	डिण्डौरी	1	34	28	0	0	3	
झाबुआ	40	2	0	1	29	80	झाबुआ	1	0	2	75	1	1	
खण्डवा	43	34	0	0	2	79	खण्डवा	1	1	31	44	0	2	
मंडला	0	98	1	0	0	99	मंडला	0	1	98	0	0	0	
सिवनी	0	71	5	0	1	78	सिवनी	0	35	42	0	0	1	
शिवपुरी	83	4	0	0	6	93	शिवपुरी	0	0	0	93	0	0	
कुल	184	275	17	1	80	575	कुल	3	71	201	292	1	7	
प्रतिशत	32	47 <sup>8</sup>	3 <sup>0</sup>	0 <sup>2</sup>	17	100	प्रतिशत	0 <sup>5</sup>	12 <sup>3</sup>	35 <sup>0</sup>	50 <sup>8</sup>	0 <sup>2</sup>	1 <sup>2</sup>	

इस सारिणी में दिये गये आंकड़े उत्तरदाताओं की जिलेवार वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

उपरोक्त सारणी यह स्पष्ट करती है कि लगभग 80 प्रतिशत लोगों की प्रति परिवार गेहूं की मासिक जरूरत 16 से 35 किलों के बीच में है जबकि लगभग 50.8 प्रतिशत परिवारों की चावल की मासिक जरूरत 16–35 किलो है। मतलब यह गेहूं की मांग चावल की तुलना में ज्यादा है। अगर हम गेहूं और चावल की मांग जोड़ दे तो यह साफ है कि लोगों की जरूरत सरकार द्वारा किए जा रहे 35 किलों से ज्यादा की है।

## 8-2- dʒkɪ hu rɪy dh ekə

लगभग सभी वर्गों को केरोसीन तेल चाहिए क्योंकि यह शाम को रोशनी के लिए और वक्त बेवक्त मेहमानों के आने पर चाय नाश्ता या खाना बनाने के काम आता है।

## 8-3- phuh

चीनी बहुत ही कम लोग उचित मूल्य की दुकान से खरीदते हैं क्योंकि अधिकांशतः खुले बाजार की कीमत उचित मूल्य की दुकानकी कीमत से कम है। इस वजह से लगभग 40 प्रतिशत उत्तदाताओं ने इस सवाल पर उत्तर नहीं दिए। शेष उत्तरदाताओं ने अपनी मासिक पारिवारिक जरूरत के बारे में बात की न कि उचित मूल्य से कितना मिलना चाहिए पर।

## 8-4- [kk | kʊu dh mi yɔ/krk ds fɪgkt | s dʃbu | e;

गांवों में की गई समूह चर्चाओं और इंटरव्यू के विश्लेषण के आधार पर हमने एक सारणी विकसित की है। जो साल के विभिन्न महीनों में खाद्यान्न की दूसरे स्रोतों से जरूरत का खाका खींचती हैं –

ftys	i ; kɪr [kk   kʊu oky l e;	nɪ j s   kɪr kɪ s vɪr f j Dr [kk   kʊu dh t : j r oky l e;	[kk   kʊu dh xɪk h j deh	[kk   kʊu ugha	f l p k b l
शिवपुरी	अक्टूबर–दिसम्बर	जुलाई–सितम्बर	अप्रैल से जून	दिसम्बर से मार्च	वर्ष पर आधारित
झाबुआ	अक्टूबर–दिसम्बर	जनवरी–मार्च	अप्रैल–सितम्बर	ऐसा समय नहीं आता	आंशिक व्यवस्था
धार	अप्रैल–मई नवम्बर–दिसम्बर	अक्टूबर	जनवरी, जून, जुलाई	फरवरी,–मार्च, अगस्त–सितम्बर	आंशिका व्यवस्था
खण्डवा	जनवरी–मार्च	अक्टूबर–दिसम्बर	अप्रैल–जून	जुलाई–सितम्बर	वर्षा आधारित
सिवनी	अक्टूबर–दिसम्बर	जनवरी–मार्च	अप्रैल–सितम्बर	ऐसा समय नहीं आता	आंशिका व्यवस्था और मशीनें
मण्डला	अक्टूबर–दिसम्बर	जनवरी–मार्च	अप्रैल–सितम्बर	ऐसा समय नहीं आता	आंशिका व्यवस्था और मशीनें
शुण्डौरी	कुछ गांवों में अक्टूबर दिसम्बर कुछ गांवों में नवम्बर–दिसम्बर	फरवरी, सितम्बर, अक्टूबर मार्च–अप्रैल सितम्बर–अक्टूबर	जून से सितम्बर जून से अगस्त	मार्च–अप्रैल मई–जून	आंशिका व्यवस्था और मशीनें

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004

## 8-5- [kk | kʊu | g {kk vkʃ | i yk; u

लोग बताते हैं कि खाद्यान्न की कमी ही उन्हें पलायन के लिए मजबूर करती है और यह समय होता है जब उन्हें स्थानीय स्तर पर कोई मजदूरी भी उपलब्ध नहीं हो पाती। ज्यादातर गांवों में लोगों ने यही बताया कि जब भी खाद्यान्न का संकट हो या लोगों को जरूरत हो गांव में या गांव के आस–पास कोई काम शुरू नहीं होता। लोगों का यह अनुभव इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि लक्षित

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोजगार के कार्यक्रमों में समन्वय का स्तर क्या है? इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि रोजगार सृजन के कार्यक्रमों और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब तक समन्वय से काम नहीं करेंगे लोगों को वास्तव में कोई भी फायदा नहीं होगा। रोजगार सृजन के कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के माध्यम से लोगों तक अनाज और नगद पहुँचा कर लोगों को जरूरत के समय उचित मूल्य की दुकान तक पहुँचाने लायक बना सकते हैं।

## 9- mfpr eW; dh ncku vki ykx

### 1- dher ds ckjs ea tkudkj h

गांवों में लोगों से बात करते समय हमने महसूस किया कि अगर लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रणाली के संचालन की व्यवस्था, हितग्राहियों के अलग-अलग वर्गों के लिए तय कीमत, दुकान से जुड़े लोगों के अधिकार पंचायत और ग्राम सभा के अधिकार और भूमिका के बारे में ठीक-ठीक पता हो तो लक्षित वितरण प्रणाली का संचालन और लोगों की जिन्दगी पर उसका असर बहुत प्रभावी हों।

लोगों के जवाबों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 87.5 प्रतिशत लोगों को यह पता है कि उचित मूल्य की दुकान पर सस्ता अनाज मिलता है। 9.2 प्रतिशत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। अन्त्योदय, गरीबी रेखा और गरीबी रेखा से ऊपर सभी वर्गों के औसतन 80 प्रतिशत से ज्यादा हितग्राही यह बताते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी है।

mfpr eW; dh ncku ij   Lrs njk ij vukt dh miy/krk dh tkudkj h			
ftys	gka	ugha	tokc ugha
धार	270,15 <sup>६</sup> ₹	4,2 <sup>२</sup> ₹	6,9 <sup>५</sup> ₹
डिण्डोरी	258,14 <sup>९</sup> ₹	7,3 <sup>९</sup> ₹	4,6 <sup>३</sup> ₹
झाबुआ	209,12 <sup>९</sup> ₹	75,41 <sup>२</sup> ₹	10,15 <sup>९</sup> ₹
खण्डवा	245,14 <sup>२</sup> ₹	29,15 <sup>९</sup> ₹	16,25 <sup>६</sup> ₹
मंडला	226,13 <sup>९</sup> ₹	41,22 <sup>५</sup> ₹	12,19 <sup>५</sup> ₹
सिवनी	254,14 <sup>९</sup> ₹	11,6 <sup>०</sup> ₹	13,20 <sup>६</sup> ₹
शिवपुरी	263,15 <sup>२</sup> ₹	15,8 <sup>२</sup> ₹	2,3 <sup>१</sup> ₹
कुल	1725,87 <sup>५</sup> ₹	182,9 <sup>४</sup> ₹	63,3 <sup>२</sup> ₹

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

इसी सवाल को जब आगे बढ़ा कर पूछा गया कि क्या उन्हें

यह पता रहता है कि उचित मूल्य की दुकान पर कब कितना स्टॉक है और उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध सामानों की कीमत क्या है तब परिस्थिति बदल जाती है। 65.6 प्रतिशत लोगों को स्टॉक कीमत के बारे में नहीं पता है। 12.2 प्रतिशत लोग हमें नहीं मालूम बोलकर जवाब नहीं देते और 9.8 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्हें कभी-कभी पता चल जाता है।

mfpr eW; dh ncku ds ckjs ea tkudkj h				
ftys	gka	ugha	Dhk&dHk	tokc ugha
धार	27 <sup>६</sup>	16 <sup>९</sup>	0 <sup>५</sup>	2 <sup>९</sup>
डिण्डोरी	10 <sup>३</sup>	17 <sup>४</sup>	0 <sup>०</sup>	7 <sup>९</sup>
झाबुआ	27 <sup>२</sup>	8 <sup>९</sup>	63 <sup>४</sup>	0 <sup>४</sup>
खण्डवा	4 <sup>९</sup>	4 <sup>२</sup>	35 <sup>६</sup>	65 <sup>९</sup>
मंडला	9 <sup>९</sup>	18 <sup>३</sup>	0 <sup>५</sup>	8 <sup>३</sup>
सिवनी	17 <sup>९</sup>	15 <sup>३</sup>	0 <sup>०</sup>	15 <sup>४</sup>
शिवपुरी	4 <sup>९</sup>	20 <sup>९</sup>	0 <sup>०</sup>	0 <sup>९</sup>
कुल	12 <sup>३</sup>	65 <sup>६</sup>	9 <sup>९</sup>	12 <sup>२</sup>

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

पंचायत का सचिव, कोटवार, गांव के दूसरे लोग, राशन दुकान का संचालन तथा अन्य लोग जैसे सरकारी कर्मचारी पंच-सरपंच आदि से लोगों को उचित मूल्य की दुकान के बारे में सूचना मिलती है। 91.8 प्रतिशत लोगों ने बताया कि दुकान से बात करने पर वह बहुत से सवाल पूछता है या धमकी देना शुरू कर देता है जैसे -

- आपको हमसे सवाल पूछने का क्या अधिकार है।
- सरकारी जानकारी गोपनीय होती है।
- क्यों जानना चाहते हो।
- बदतमीजी कर देता है।
- यह जानकारी लेकर क्या करेंगे।
- आप अपना काम बताइये आपको दुनिया से क्या लेना-देना आदि

## 10- forj.k iz kkyh ds ykHk

बहुत से लोग या परिवार लक्षित वितरण प्रणाली पर निर्भर रहते हैं और उम्मीद का दामन थामे रहते हैं। लोगों के दिल में एक उम्मीद रहती है कि शायद यह व्यवस्था एक दिन उनकी अनाज से जुड़ी जरूरत पूरी करेगी और शायद इसलिए वे इस व्यवस्था, इसकी दुकाने, अनाज की गुणवत्ता और दूसरी समस्याओं को ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं। इस प्रणाली को उपयोगिता के बारे में विभिन्न जिलों के हितग्राहियों के विचार नीचे सारणी में प्रस्तुत किए गए हैं।

mfpr eW; dh nqku l s [kjhn				
जिले का नाम	हां	नहीं	कभी-कभी	जवाब नहीं
धार	181,13 <sup>३०</sup> द	37,18 <sup>१०</sup> द	58,17 <sup>३०</sup> द	4,6 <sup>२०</sup> द
डिण्डोरी	218,16 <sup>द</sup>	23,11 <sup>३३</sup> द	24,7 <sup>२०</sup> द	4,6 <sup>२०</sup> द
झाबुआ	184,13 <sup>१६</sup> द	5,20 <sup>६</sup> द	95,28 <sup>१४</sup> द	10,15 <sup>१४</sup> द
खण्डवा	248,18 <sup>२२</sup> द	11,5 <sup>१४</sup> द	18,5 <sup>१४</sup> द	13,20 <sup>द</sup>
मंडला	172,12 <sup>१६</sup> द	10,4 <sup>१०</sup> द	83,24 <sup>१८</sup> द	14,21 <sup>१६</sup> द
सिवनी	203,14 <sup>१९</sup> द	24,11 <sup>१८</sup> द	35,10 <sup>१४</sup> द	16,24 <sup>१६</sup> द
शिवपुरी	160,11 <sup>१७</sup> द	94,46 <sup>११</sup> द	22,6 <sup>१०</sup> द	4,6 <sup>२०</sup> द
कुल	1366,69 <sup>३३</sup> द	204,10 <sup>१४</sup> द	335,17 <sup>१०</sup> द	65,3 <sup>१३</sup> द

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

Mfpr eW; dh nqku l s feyus okys vukt l s ijh gkus okyh i kfjokfd t: jr				
t: jr ijh gkus dh vof/k	xjhch jskk Js kh ds dkmZ /kkjd	vR; n; Js kh ds dkmZ /kkjd	xjhch jskk l s dy Aij dh Js kh ds dkmZ /kkjd	
पूरे साल	7 <sup>१</sup>	16 <sup>९</sup>	1 <sup>१</sup>	9 <sup>२</sup>
लगभग 6 से 9 महीनों तक	11 <sup>१०</sup>	18 <sup>१६</sup>	1 <sup>९</sup>	11 <sup>१३</sup>
लगभग 3 से 6 महीनों तक	38 <sup>१६</sup>	44 <sup>१९</sup>	10 <sup>१०</sup>	36 <sup>१४</sup>
लगभग 1 से 3 महीनों तक	22 <sup>१३</sup>	15 <sup>११</sup>	4 <sup>१८</sup>	17 <sup>१८</sup>
कभी-कभी	13 <sup>१८</sup>	1 <sup>१०</sup>	55 <sup>१८</sup>	15 <sup>१८</sup>
इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते	3 <sup>१४</sup>	0 <sup>१९</sup>	23 <sup>१८</sup>	5 <sup>१४</sup>
यह सुविधा लाभकारी नहीं है	1 <sup>१६</sup>	0 <sup>१६</sup>	0 <sup>१४</sup>	1 <sup>११</sup>
जवाब नहीं	2 <sup>१२</sup>	2 <sup>११</sup>	2 <sup>१२</sup>	2 <sup>१२</sup>

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

ऊपर से देखें तो यह साफ होता है कि 9.2 प्रतिशत लोगों की साल भर की जरूरत उनके अपने उत्पादन और लक्षित वितरण प्रणाली की दुकान से हो जाता है। शेष 90.8 प्रतिशत लोगों को अपने उत्पादन उचित मूल्य की दुकान के साथ-साथ दूसरे श्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। अंत्योदय वर्ग के 16.9 प्रतिशत हितग्राही अपने दूसरे श्रोतों और उचित मूल्य की दुकान से लिये राशन में अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं। लगभग 60 प्रतिशत अंत्योदय वर्ग के लोग अपने श्रोत और उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले अनाज के सहारे 1 से 6 महीनों तक टिके रहते हैं। गरीबी रेखा के ऊपर के 7.2 प्रतिशत हितग्राही किसी न किसी से लक्षित वितरण प्रणाली या तो उपयोग नहीं करते या उपयोगी नहीं मानते। गरीबी रेखा के ऊपर के 23.8 प्रतिशत हितग्राही इस सुविधा का उपयोग नहीं करते। गरीबी रेखा के नीचे वाले कार्डधारियों में से 1.6 प्रतिशत हितग्राही उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाले राशन की व्यवस्था को अनुपयोगी मानते हैं।

## 11- mfpr eW; dh nqku l s [kjhn

हमाने यह पता लगाने की कोशिश की कितने लोग उचित मूल्य की दुकान से अनाज खरीदते हैं पता चला कि कुल उत्तरदाताओं में से 69.3 प्रतिशत लोग उचित मूल्य की दुकान से अनाज लेते हैं। इस 67.3 प्रतिशत में सबसे ज्यादा लोग अंत्योदय वर्ग के (कुल अंत्योदय का 93 प्रतिशत) फिर गरीबी रेखा के नीचे वाले वर्ग (कुल गरीबी रेखा का 65 प्रतिशत) और सबसे कम गरीबी रेखा के ऊपर के (लगभग 38 प्रतिशत) लोग राशन की दुकान से अनाज लेते हैं।

10.4 प्रतिशत लोग राशन की दुकान से अनाज नहीं लेते और लगभग 17 प्रतिशत लोग कभी-कभी अनाज लेने जाते हैं। 3.3 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे राशन की दुकान नहीं जाते और इस कारण वे इस सवाल पर चुप रहे।

### 11-1- mfpr eW; ds nqku ij oLrqvks dh dhers

हमने अलग-अलग वर्ग के कार्ड धारकों से यह जानने का प्रयास किया कि उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध वस्तुएं उन्हें किस कीमत पर मिलती है।

#### vR; kn; oxL

- इस वर्ग के 98.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि उन्हें गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है।
- 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि उन्हें चावल 3 रुपये प्रतिकिलो की दर से मिलता है। लगभग 7.2 प्रतिशत उत्तरदाता किसी न किसी कारण से उचित मूल्य की दुकान से राशन नहीं लेते।
- लगभग 84.2 प्रतिशत लोगों के अनुसार चीनी की कीमत 9 रुपये प्रति किलो से ज्यादा है। 15.4 प्रतिशत उत्तरदाता चीनी नहीं लेते।
- 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि केरोसीन की कीमत 9 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा है।

यानि कुल मिलाकर देखे तो अधिकांश लोगों को उचित मूल्य की दुकान पर अनाज तय कीमत पर उपलब्ध है।

mfpr eW; dh nqku ij vR; kn; dkMZ /kkfj; ks l sfofHku ol rrvks ds fy, yh tkus okyh dher												
oLrq	nqku ij l keku dh dher tks l keku [kjhns oDr pdkuh i Mrh gS %dkVd ea fn; s x; s vad i fr'kr crkrs gS %											
	[knhns ugha	irk ugha	, d #i; s	nks #i; s	rhu #i; s	pkj #i; s	lkkp #i; s	N% #i; s	l kr #i; s	vkB #i; s	ukS #i; s	ukS #i; s l s T; knk
चावल	7 ,1 <sup>१२</sup> द	34 ,5 <sup>१९</sup> द	0 ,0द	7 ,1 <sup>१२</sup> द	437 ,76द	3 ,0 <sup>१५</sup> द	5 ,0 <sup>१९</sup> द	13 ,2 <sup>१३</sup> द	20 ,3 <sup>१५</sup> द	4 ,0 <sup>१७</sup> द	0 ,0द	45 ,7 <sup>१८</sup> द
गेहूँ	0 ,0 <sup>१०</sup> द	1 ,0 <sup>१२</sup> द	1 ,0 <sup>१२</sup> द	564 ,98 <sup>१४</sup> द	2 ,0 <sup>१३</sup> द	0 ,0द	5 ,0 <sup>१९</sup> द	1 ,0 <sup>१२</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0 <sup>१२</sup> द	1 ,0 <sup>१२</sup> द
शक्कर	33 ,5 <sup>१७</sup> द	56 ,9 <sup>१७</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	2 ,0 <sup>१३</sup> द	484 ,84 <sup>१२</sup> द
केरोसिन	2 ,0 <sup>१३</sup> द	8 ,1 <sup>१४</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	2 ,0 <sup>१३</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	162 ,28 <sup>१२</sup> द	401 ,69 <sup>१७</sup> द
अन्य	42 ,7 <sup>१३</sup> द	10 ,1 <sup>१७</sup> द	0 ,0द	1 ,0 <sup>१२</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	522 ,90 <sup>१८</sup> द

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

#### xjhch js[kk dkMZ /kkjh

मध्यप्रदेश में गरीबी रेखा कार्डधारियों के लिए उचित मूल्य की दुकान पर गेहूँ 5 रुपये प्रति किलो और चावल 6 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध होना चाहिए।

- लगभग 9.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें चावल 6 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है। 66.43 प्रतिशत लोगों का जवाब था कि उन्हें चावल 7 रुपये प्रतिकिलो की दर से मिलता है। लगभग 15 प्रतिशत लोगों को चावल 8 रुपये या उससे ज्यादा कीमत पर मिलता है।
- 85.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को गेहूँ 5 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है। लगभग 2.68 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें गेहूँ 6 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है। गरीबी रेखा वर्ग के 4.53 प्रतिशत उत्तरदाता उचित मूल्य की दुकान से गेहूँ नहीं लेते और 5.89 प्रतिशत लोगों को गेहूँ 9 रुपये से ज्यादा कीमत पर मिलता है।

- 28.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं को केरोसीन 9 रुपये प्रतिलीटर की दर से और 68.44 प्रतिशत उत्तरदाताओं को केरोसीन 9 रुपये से ज्यादा की दर पर मिलता है।
- 97.77 प्रतिशत उत्तर दाताओं की चीनी 13 रुपये प्रतिकिलो की दर से मिलती है।

आंकड़े यह बताते हैं कि चावल का वितरण ठीक कीमत पर नहीं हो रहा और उसमें गड़बड़ी है।

mfpr eW; dh nqku ij xjhch js[kk dkmZ /kkfj; k s fofHku ol rpk ds fy, yh tkus okyh dher													
olrq	nqku ij l keku dh dher tks l keku [kjhns oDr pdkuh i Mfh gS %dks Vd ea fn; s x; s vad i fr'kr crkrs gS ½												
	[kjhns ugha	irk ugha	, d #i ; s	nks #i ; s	rhu #i ; s	pkj #i ; s	lkp #i ; s	N% #i ; s	l kr #i ; s	vkB #i ; s	uks #i ; s	uks #i ; s l s T; knk	
चावल	9 ,0 <sup>80</sup> द	79 ,7 <sup>05</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	6 ,0 <sup>54</sup> द	0 ,0द	1 ,0 <sup>09</sup> द	110 ,9 <sup>82</sup> द	744 ,66 <sup>43</sup> द	14 ,1 <sup>25</sup> द	9 ,0 <sup>80</sup> द	148 ,13 <sup>21</sup> द	
गेहूँ	16 ,1 <sup>43</sup> द	35 ,3 <sup>13</sup> द	0 ,0द	8 ,0 <sup>71</sup> द	2 ,0 <sup>18</sup> द	2 ,0 <sup>18</sup> द	960 ,85 <sup>71</sup> द	30 ,2 <sup>68</sup> द	1 ,0 <sup>09</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	66 ,5 <sup>89</sup> द	
शक्कर	26 ,2 <sup>23</sup> द	99 ,8 <sup>84</sup> द	0 ,0द	3 ,0 <sup>27</sup> द	1 ,0 <sup>09</sup> द	2 ,0 <sup>18</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	1 ,0 <sup>09</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	988 ,88 <sup>21</sup> द	
केरोसिन	4 ,0 <sup>36</sup> द	15 ,1 <sup>34</sup> द	2 ,0 <sup>18</sup> द	0 ,0द	1 ,0 <sup>09</sup> द	1 ,0 <sup>09</sup> द	2 ,0 <sup>18</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	324 ,28 <sup>93</sup> द	771 ,68 <sup>84</sup> द	
अन्य	2 ,0 <sup>18</sup> द	21 ,1 <sup>88</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	1 ,0 <sup>09</sup> द	1 ,0 <sup>09</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	1095 ,97 <sup>77</sup> द	

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

### xjhch js[kk ds Åij ds fgrxkgh

- इस वर्ग के 17.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें चावल 9 या 9 रुपये से कम कीमत पर मिल जाता है। 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं को चावल 9 रुपये से ज्यादा कीमत पर मिलता है। सरकार द्वारा तय रेट रु. 9.20 प्रतिकिलो है। 31.4 प्रतिशत उत्तरदाता उचित मूल्य की दुकान से चावल नहीं लेते।
- गरीबी रेखा से ऊपर के हितग्राहियों के लिए उचित मूल्य की दुकान पर गेहूँ की कीमत 7 रुपये प्रति किलो तय है। 18.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस कीमत या गेहूँ मिलता है। 15 प्रतिशत उत्तर दाताओं को 7 रुपये से कम कीमत पर मिलता है और 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं को गेहूँ 9 रुपये से ज्यादा की कीमत पर गेहूँ मिलता है।
- 7.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं को केरोसीन 9 रुपये प्रति लीटर और 79.6 प्रतिशत को 9 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा की दर पर मिलता है।
- 33.5 प्रतिशत उत्तरदाता चीनी नहीं खरीदते और 79.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के हिसाब से चीनी की कीमत 13 रुपये के आस-पास है।

mfpr eW; dh nqku ij xjhch js[kk dkmZ /kkfj; k s fofHku ol rpk ds fy, yh tkus okyh dher													
olrq	nqku ij l keku dh dher tks l keku [kjhns oDr pdkuh i Mfh gS %dks Vd ea fn; s x; s vad i fr'kr crkrs gS ½												
	[kjhns ugha	irk ugha	, d #i ; s	nks #i ; s	rhu #i ; s	pkj #i ; s	lkp #i ; s	N% #i ; s	l kr #i ; s	vkB #i ; s	uks #i ; s	uks #i ; s l s T; knk	
चावल	30 ,11 <sup>2</sup> द	54 ,20 <sup>1</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	23 ,8 <sup>6</sup> द	8 ,3 <sup>0</sup> द	17 ,6 <sup>23</sup> द	137 ,50 <sup>9</sup> द	
गेहूँ	44 ,16 <sup>4</sup> द	47 ,17 <sup>5</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,2द	14 ,5 <sup>2</sup> द	21 ,7 <sup>8</sup> द	49 ,18 <sup>2</sup> द	12 ,4 <sup>5</sup> द	1 ,0 <sup>4</sup> द	81 ,30 <sup>1</sup> द	
शक्कर	39 ,14 <sup>5</sup> द	51 ,19 <sup>0</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	1 ,0 <sup>4</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	178 ,66 <sup>2</sup> द	
केरोसिन	20 ,7 <sup>4</sup> द	12 ,4 <sup>5</sup> द	2 ,0 <sup>7</sup> द	1 ,0 <sup>4</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	20 ,7 <sup>4</sup> द	214 ,79 <sup>6</sup> द	
अन्य	28 ,10 <sup>4</sup> द	8 ,3 <sup>0</sup> द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	0 ,0द	233 ,86 <sup>6</sup> द	

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

### 11-2- mfpr eW; dh nqku l s f'kdk; r

राशन की ठीक कीमत पर न मिलना दुकान का समय पर न खुलना जैसे बहुत सारे मुद्दे लोग अक्सर गांवों में उठाते रहे। हमने इस अध्ययन में इन शिकायतों का विस्तृत विश्लेषण करने का प्रयास किया है।

अध्ययन में उत्तर दाताओं के जवाबों का विश्लेषण बताता है कि 41.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं को उचित मूल्य की दुकान से शिकायत है और 58.38 प्रतिशत लोगों को शिकायत नहीं है। शिकायत के इस विश्लेषण से पहले यह बात दुहराना उचित होगा कि 65.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के उचित मूल्य की दुकान के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है और लगभग 9.42 प्रतिशत उत्तरदाताओं को यह भी नहीं पता कि उचित मूल्य की दुकान पर अंत्योदय वर्ग के लिए गेहूँ 2 रुपये प्रतिकिलो और चावल 3 रुपये प्रतिकिलो उपलब्ध है। जानकारी का यह अभाव लोगों की शिकायतों का प्रतिशत अपने आप कम कर देता है।

शिवपुरी के 98 प्रतिशत उत्तरदाताओं को राशन की दुकान से शिकायत है और झाबुआ के 61 प्रतिशत उत्तरदाता उचित मूल्य की दुकान से संतुष्ट है। जिन उत्तरदाताओं को शिकायत है उनमें से 15.2 प्रतिशत लोग ही अपनी शिकायत को लेकर ऊपर के अधिकारियों तक गए हैं। 84.7 प्रतिशत लोगों ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। जिन लोगों को शिकायत है उन्होंने दर्ज भी कराया है। उनमें से सबसे ज्यादा 60 प्रतिशत लोग डिण्डोरी के हैं फिर 16 प्रतिशत शिवपुरी और सिवनी में 15.4 प्रतिशत है।

यह आंकड़े इस बात का उल्लेख करते हैं कि अधिकांश स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने का काम भी लगभग न के बराबर है।

mfpr eW; I sf'kdk; r			
ftys dk uke	gka	ugha	dy
धार	87 31 <sup>007</sup>	193 68 <sup>993</sup>	280
डिण्डोरी	42 15 <sup>773</sup>	225 84 <sup>227</sup>	267
झाबुआ	181 61 <sup>566</sup>	113 38 <sup>444</sup>	294
खण्डवा	58 20 <sup>449</sup>	225 79 <sup>551</sup>	283
मंडला	2 0 <sup>772</sup>	275 99 <sup>228</sup>	277
सिवनी	108 38 <sup>999</sup>	169 61 <sup>001</sup>	277
शिवपुरी	276 98 <sup>557</sup>	4 1 <sup>443</sup>	280
कुल	815 41 <sup>562</sup>	1143 58 <sup>338</sup>	1958

जिलों के नीचे वाले खानों में जवाब देने वालों का प्रतिशत दिया गया है  
 श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

### 11-2-1- f'kdk; r ntZ djkus ds LFkku

उचित मूल्य की दुकान की समस्याओं से परेशान लोग अपनी शिकायतें लेकर कई जगह जाते हैं जैसे कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, विकास खण्ड अधिकारी, जिला पंचायत आदि। हमने आंकड़ों के विश्लेषण से यह जानने की कोशिश की कि सबसे ज्यादा किस जगह पर शिकायतें दर्ज होती हैं। परिणाम यह बताते हैं कि सबसे ज्यादा शिकायतें लेकर लोग ग्राम पंचायत के पास जाते हैं। गरीबी रेखा के उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत अंत्योदय के उत्तरदाताओं में से 43 प्रतिशत और गरीबी रेखा से ऊपर के उत्तरदाताओं में से 62.5 प्रतिशत लोग ग्राम पंचायत जाते हैं अंत्योदय के 33 प्रतिशत लोग और गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले 12.5 प्रतिशत लोग विकास खण्ड अधिकारी के पास जाते हैं। विस्तृत परिणाम नीचे चारणी में दिए गए हैं।

f'kdk; r ntZ djokus ds LFkku			
f'kdk; r ntZ djokus ds LFkku	xjhch j'kdk; r ntZ djokus ds LFkku	Vk; n; J'sth ds LFkku	xjhch j'kdk; r ntZ djokus ds LFkku
ग्राम पंचायत	72	43 <sup>93</sup>	62 <sup>55</sup>
जनपद पंचायत	6	3 <sup>93</sup>	16 <sup>77</sup>
विकास खण्ड अधिकारी	2	33 <sup>93</sup>	12 <sup>55</sup>
जिला पंचायत	8	10	4 <sup>92</sup>
जिला खाद्य अधिकारी	2	3 <sup>93</sup>	0 <sup>90</sup>
कलेक्टर	8	6 <sup>97</sup>	4 <sup>92</sup>
राज्य स्तर पर	2	0	0 <sup>90</sup>

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

### 11-2-2- f'kdk; r ugha ntZ djkus

जो लोग उचित मूल्य की दुकान की समस्याओं से परेशान है और शिकायत नहीं दर्ज कराते उनके अनुभव बहुत सी अनकही पहलुओं को उजागर करते है मसलन 20 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि शिकायतें करने से कोई फायदा नहीं। 35.74 प्रतिशत लोगों को यह पता ही नहीं है कि समस्याओं को लेकर कहाँ जाएँ क्या करें। लगभग 7.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं को समस्या निवारण में किसी से कोई मदद नहीं मिलती है।

f'kdk; r ugha nt/ djokus dk dkj .k						
ftys dk uke	gejih ckr dh i uolbi ugha	ge dls Yugh ekyee D; k duuk	Dkol enn ugha djrk	vl;	tokc ugha	
घार	8 <sup>०</sup>	8 <sup>०</sup>	6 <sup>५</sup>	3 <sup>१</sup>	35 <sup>५</sup> 8	
डिण्डोरी	23 <sup>५</sup>	17 <sup>५</sup>	24 <sup>२</sup>	3 <sup>५</sup>	1 <sup>२</sup> 3	
झाबुआ	16 <sup>१</sup>	14 <sup>५</sup>	9 <sup>२</sup>	46 <sup>५</sup>	1 <sup>२</sup> 8	
खण्डवा	5 <sup>८</sup>	6 <sup>५</sup>	3 <sup>९</sup>	10 <sup>५</sup>	48 <sup>९</sup> 7	
मंडला	0 <sup>०</sup>	29 <sup>५</sup>	23 <sup>५</sup>	15 <sup>५</sup>	0 <sup>०</sup> 0	
सिवनी	18 <sup>३</sup>	8 <sup>५</sup>	17 <sup>५</sup>	17 <sup>३</sup>	16 <sup>३</sup> 6	
शिवपुरी	28 <sup>१</sup>	15 <sup>१</sup>	15 <sup>०</sup>	2 <sup>७</sup>	8 <sup>५</sup> 6	
कुल	0 <sup>२</sup> 20	35 <sup>७</sup> 74	7 <sup>७</sup> 7	11 <sup>५</sup> 47	24 <sup>९</sup> 82	

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

## 12- mfpr eW; dh ndku ugha tkuk

लगभग 52 प्रतिशत उत्तरदाता कई बार उचित मूल्य की दुकान से राशन नहीं खरीदना चाहते या नहीं खरीदते। इतनी बड़ी तादात में लोग अगर उचित मूल्य की दुकान पर नहीं जाना चाहते तो यह पूरी व्यवस्था पर एक बड़ी तल्ख टिप्पणी है और हमें लगा कि इसके कारणों की विस्तार से विवेचना होनी चाहिए।

- लगभग 9.67 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले राशन की गुणवत्ता ठीक नहीं है। अंत्योदय वर्ग के शिवपुरी के 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं की शिकायत है कि उन्हें खराब अनाज मिलता है।
- 5.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि चूँकि दुकानदार उनके साथ बुरा बर्ताव करता है इसलिए वे उचित मूल्य की दुकान जाना या वहाँ से राशन लेना पसन्द नहीं करते।
- उचित मूल्य की दुकान घर से दूर होने की वजह से 19.4 प्रतिशत लोग राशन की दुकान से अनाज खरीदी को प्राथमिकता नहीं देते।
- किशतों में राशन नहीं मिलने की वजह से 10.39 प्रतिशत उत्तरदाता राशन की दुकान से राशन नहीं दरीद पाते। यह स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का खुला उल्लघन है।
- जरूरत के दिनों में राशन की दुकान खुली नहीं होती और इस कारण 7.49 प्रतिशत लोग दुकान नहीं जा पाते। यह भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का खुला उल्लखन है।
- 13.54 प्रतिशत उत्तरदाता बताते है कि उनका खुद का उत्दान उनकी जरूरत के लिए काफी है। झाबुआ के अंत्योदय वर्ग के 28 प्रतिशत हितग्राहियों, गरीबीरेखा के 44 प्रतिशत और गरीबी रेखा के ऊपर के 100 प्रतिशत लोगों को अपना खुद का अनाज उत्पादन उनकी जरूरत भर के लिए काफी है अतः वे उचित मूल्य की दुकान नहीं जाते।
- 5.35 प्रतिशत लोगों को कहना था कि राशन की दुकान पर अनाज उपलब्ध ही नहीं होता तो वो दुकान जाकर क्या करेंगे। झाबुआ के अंत्योदय वर्ग के 13.8 प्रतिशत लोगों का यह अनुभव है, सिवनी के गरीबी रेखा वर्ग के 7.5 प्रतिशत लोगों का और शिवपुरी के इसी वर्ग के 27 प्रतिशत लोगों को अनुभव भी समान है।

tkudkjh ekxus ij nplkunj dh ifrf0; k							
ftys dk uke	rpgs; g tkudkjh yus dk D; k vf/kdkj gS	; g xki uh; tkudkjh gS	D; ka tkuuk pkgrs gks	/kedh nuk ; k nq D; ogkj djuk	enn djuk	vl;	tokc ugha
घार	3 <sup>८</sup>	9 <sup>८</sup>	26 <sup>५</sup>	1 <sup>७</sup>	28 <sup>८</sup>	13 <sup>९</sup>	8 <sup>८</sup>
डिण्डोरी	2 <sup>८</sup>	4 <sup>९</sup>	7 <sup>०</sup>	0 <sup>०</sup>	3 <sup>८</sup>	31 <sup>७</sup>	1 <sup>५</sup>
झाबुआ	4 <sup>२</sup>	2 <sup>५</sup>	5 <sup>०</sup>	7 <sup>५</sup>	31 <sup>८</sup>	29 <sup>३</sup>	3 <sup>५</sup>
खण्डवा	0 <sup>५</sup>	4 <sup>९</sup>	0 <sup>०</sup>	0 <sup>०</sup>	1 <sup>५</sup>	4 <sup>५</sup>	58 <sup>१</sup>
मंडला	0 <sup>०</sup>	0 <sup>०</sup>	33 <sup>८</sup>	11 <sup>०</sup>	2 <sup>३</sup>	15 <sup>८</sup>	1 <sup>५</sup>
सिवनी	11 <sup>३</sup>	29 <sup>३</sup>	15 <sup>८</sup>	52 <sup>५</sup>	26 <sup>५</sup>	4 <sup>५</sup>	26 <sup>५</sup>
शिवपुरी	77 <sup>५</sup>	48 <sup>८</sup>	12 <sup>२</sup>	27 <sup>१</sup>	5 <sup>३</sup>	0 <sup>१</sup>	0 <sup>७</sup>
कुल	11 <sup>८</sup>	2 <sup>९</sup>	24 <sup>७</sup>	6 <sup>५</sup>	7 <sup>३</sup>	39 <sup>१</sup>	8 <sup>२</sup>

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

लोगों ने उचित मूल्य की दुकान कम इस्तेमाल की कुछ और वजहे भी बतायी है जैसे –

- 25.94 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार दुकानदार राशन को खुले बाजार में बेच देता है।

- 7.11 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार दुकानदार अच्छा राशन बेचता है और खराब राशन दुकान पर रखता है।
- 8.33 प्रतिशत लोगों के अनुसार दुकानदार कमी अनाज देता है तो कभी मना कर देता है।

कुल मिलाकर लगभग 50.44 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि दुकानदार उन्हें अनाज न देने के लिए तरह-तरह के हथकड़े अपनाता है।

mfpr eW; dh nplku ij de tkus dh otg								
nplkunj }kjk dh tkus okyh vfuferRk; a								
ftys dk uke	vPNk vukt [kys cktkj ea Hkst fn; k tkrk gS vkg [kjk vukt nplku ij	dkM/ /kfj; ka dks [kjk vukt nrs gS vkg vPNk vukt cpk dj j [krs gS	DHk nrs gS dHkh ugha nrs gS	vli;	dkbZ ugha	dkbZ Li "V dkj .k ugha crk l drs	tokc ugha	dy
धार	12 <sup>92</sup>	4 <sup>29</sup>	31 <sup>52</sup>	0 <sup>98</sup>	14 <sup>29</sup>	9 <sup>52</sup>	16 <sup>40</sup>	14 <sup>21</sup>
डिण्डोरी	0 <sup>78</sup>	7 <sup>86</sup>	1 <sup>82</sup>	0 <sup>00</sup>	0 <sup>00</sup>	19 <sup>05</sup>	26 <sup>82</sup>	13 <sup>65</sup>
झाबुआ	15 <sup>85</sup>	45 <sup>71</sup>	11 <sup>52</sup>	62 <sup>44</sup>	0 <sup>00</sup>	4 <sup>76</sup>	0 <sup>11</sup>	14 <sup>92</sup>
खण्डवा	3 <sup>52</sup>	1 <sup>43</sup>	0 <sup>00</sup>	2 <sup>44</sup>	14 <sup>29</sup>	47 <sup>62</sup>	27 <sup>58</sup>	14 <sup>72</sup>
मंडला	0 <sup>00</sup>	0 <sup>00</sup>	1 <sup>21</sup>	24 <sup>39</sup>	14 <sup>29</sup>	9 <sup>52</sup>	24 <sup>32</sup>	14 <sup>16</sup>
सिवनी	31 <sup>90</sup>	5 <sup>00</sup>	25 <sup>45</sup>	9 <sup>27</sup>	57 <sup>14</sup>	4 <sup>76</sup>	4 <sup>56</sup>	14 <sup>11</sup>
शिवपुरी	35 <sup>03</sup>	35 <sup>71</sup>	28 <sup>48</sup>	0 <sup>49</sup>	0 <sup>00</sup>	4 <sup>76</sup>	0 <sup>22</sup>	14 <sup>21</sup>
कुल	511 (25.94)	140 (7.11)	165 (8.33)	205 (10.41)	7 (0.36)	21 (1.1)	921 (46.75)	1970 (100)
श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004								

### 13- mfpr eW; ds nplku [kqyus dh vof/k vkg l e;

उचित मूल्य की दुकान कितने समय के लिए खुलती है यह तथा अपने आप में उसके कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कर देता है। हमने तीनों वर्गों के कार्डधारियों से यह जानना चाहा तो

- 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी दुकान महीने में 2-5 दिन खुलती है।
- 34.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी दुकान महीने में 5 से 10 दिन तक खुलती है।
- 20.8 प्रतिशत लोगों के अनुसार उनकी दुकान 10 से 15 दिन तक खुलती है।

Eghus ea nplku [kqyus ds fnu						
ftys dk uke	2 से 5 दिन	5 से 10 दिन	10 से 15 दिन	15 से 20 दिन	पूरा महीना	नहीं जानते
धार	17 <sup>91</sup>	1 <sup>96</sup>	43 <sup>94</sup>	0 <sup>90</sup>	0 <sup>90</sup>	0 <sup>90</sup>
डिण्डोरी	13 <sup>90</sup>	16 <sup>90</sup>	7 <sup>93</sup>	0 <sup>90</sup>	18 <sup>92</sup>	85 <sup>90</sup>
झाबुआ	0 <sup>99</sup>	24 <sup>90</sup>	3 <sup>97</sup>	0 <sup>90</sup>	76 <sup>92</sup>	0 <sup>90</sup>
खण्डवा	0 <sup>99</sup>	13 <sup>91</sup>	11 <sup>95</sup>	89 <sup>92</sup>	1 <sup>94</sup>	12 <sup>95</sup>
मंडला	26 <sup>96</sup>	10 <sup>99</sup>	15 <sup>91</sup>	0 <sup>90</sup>	0 <sup>90</sup>	2 <sup>95</sup>
सिवनी	37 <sup>99</sup>	11 <sup>92</sup>	0 <sup>90</sup>	0 <sup>90</sup>	0 <sup>90</sup>	0 <sup>90</sup>
शिवपुरी	3 <sup>96</sup>	23 <sup>93</sup>	19 <sup>90</sup>	10 <sup>98</sup>	4 <sup>92</sup>	0 <sup>90</sup>
कुल	27 <sup>90</sup>	34 <sup>99</sup>	20 <sup>98</sup>	8 <sup>90</sup>	7 <sup>93</sup>	2 <sup>90</sup>
श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004						

- 15.3 प्रतिशत लोगों के अनुसार उनकी दुकान महीने में 5 दिन से ज्यादा समय के लिए खुलती है और इसमें से 7.3 प्रतिशत लोगों के अनुसार उनकी दुकान महीने भर खुलती है।

उचित मूल्य की दुकान खुलने के समय के बारे में 66.8 प्रतिशत उत्तर दाताओं का यह मानना था कि उनकी दुकान दोपहर के समय खुलती है जबकि 17.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि उनकी दुकान सुबह खुलती है। धार और खण्डवा के 40 प्रतिशत से ज्यादा उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी दुकान सुबह खुलती है। विस्तृत जानकारी नीचे सारणी में दी गयी है।

mfpr eW; dh nqku [kyus dk l e;							
ftys dk uke	सुबह	दोपहर	शाम	कभी भी	लोगों की सहमति के समय तय होता है	अन्य	जवाब नहीं
धार	40%	10%	0%	0%	0%	3%	0%
डिण्डोरी	0%	19%	0%	7%	25%	0%	14%
झाबुआ	5%	20%	0%	0%	0%	4%	0%
खण्डवा	47%	5%	5%	1%	50%	19%	85%
मंडला	4%	8%	28%	0%	0%	72%	0%
शसवनी	0%	17%	0%	68%	25%	0%	0%
शिवपुरी	2%	17%	65%	22%	0%	0%	0%
बुल	17%	66%	1%	3%	0%	9%	0%

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

#### 14- fuxjkuh l fefr; ka

निगरानी समितियों की व्यवस्था को लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया। हमने सातों जिलों में जिला, जनपद और दुकान के स्तर पर समितियों का स्थिति को समझने का प्रयास किया। सभी जिले से प्राप्त जानकारी नीचे सारणी में दी गयी है।

fuxjkuh l fefr dh l fKfr			
ftys dk uke	ftyk Lrjh; l fefr	tuin Lrjh; l fefr	nqku Lrjh; l fefr
e.Myk	जिला पंचायत अध्यक्ष को पता नहीं सहकारी समिति के प्रबंधक कहते हैं लेकिन सदस्यों का नाम पता नहीं	जनपद अध्यक्ष के अनुसार नहीं बनी सहकारी समिति के अनुसार बनी है लेकिन कार्यरत नहीं है	गठन के बारे में दुकानदार और लोगों दोनों को पता नहीं है
fM. Mkjh	समिति बनी है	जनपद अध्यक्ष के अनुसार नहीं बनी सहकारी समिति के अनुसार बनी है लेकिन कार्यरत नहीं है	जानकारी उपलब्ध नहीं है
/kkj	समिति बनी है और कलेक्टर बैठक लेते हैं	गठन हुआ है लेकिन सदस्यों को जानकारी नहीं बैठक नहीं होती	निगरानी समिति नहीं बनी है
>kq/k	जिला पंचायत अध्यक्ष के अनुसार अभी कोई समिति नहीं है पहले थी। डिप्टी कलेक्टर को ज्यादा जानकारी नहीं है	जनपद अध्यक्ष के अनुसार समिति बनी है लेकिन सक्रिय नहीं है मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अनुसार कोई कार्यसमिति नहीं बनी	सरपंचों के अनुसार कोई समिति नहीं बनी
Fl ouh	जानकारी उपलब्ध नहीं है	मुख्य कार्यपाल अधिकारी जनपद पंचायत कुरई के अनुसार निगरानी समिति जनपद स्तर पर नहीं बनी बल्कि ग्राम स्तर पर बनी है	जानकारी उपलब्ध नहीं है
f'koi jh	जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के अनुसार समिति बनी है और अपना काम करती है	जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी कोलारस के अनुसार निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ और उन लोगों को पता नहीं है। अनुविभागी अधिकारी का कहना है कि समिति गठित है	दुकान स्तर पर गठन नहीं हुआ लेकिन सोसायटी के मैनेजर उनको सदस्य कौन होगा इसकी जानकारी नहीं है
[k. Mok	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी के अनुसार जिला स्तर पर समिति बनी है	निगरानी समिति बनी है	निगरानी समिति बनी है सदस्य प्रति सप्ताह जाकर जाँच करते हैं

श्रोत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन-2004

टधिकांश जिलों में निगरानी समिति की स्थिति दयनीय है। जिला स्तरीय समितियों के बारे में जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा सदस्यों को पता नहीं है हों प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में जरूर जानते हैं।

जनपद स्तर की निगरानी समितियां कही गठित है कही शायद नहीं गठित लेकिन सक्रिय कहीं भी नहीं मिली। दुकान स्तरीय समितियां अधिकांशतः गठित नहीं है। सिर्फ शिवपुरी और खण्डवा में इस स्तर पर समितियों के बारे में जानकारी मिली।

## 15- i pk; rka vkj xke I Hkk dh Hkkxhinkjh

भारत सरकार के निर्देश, सर्वोच्च न्यायलय के आदेश और भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति यह अपेक्षा करते हैं कि पूरी व्यवस्था को समक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए पंचायतों, पंचायत, प्रतिनिधियों और ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

अधिकांश जिलों में जिला स्तर पर पंचायतों, पंचायत प्रतिनिधियों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की इस व्यवस्था में सीधी भागीदारी बहुत कम देखने में आयी। झाबुआ की जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि अभी उनकी कोई भागीदारी नहीं। मण्डला जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि उन लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप अनाज का आवंटन नहीं होता।

पूरी व्यवस्था में जनपद पंचायतों की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया है लेकिन सातों जिलों में जनपद पंचायत का इस व्यवस्था में हस्तक्षेप न के बराबर था। कई जगह जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अध्यक्षों ने यही बताया कि इस व्यवस्था के बारे में एस.डी.एम. को ज्यादा जानकारी है।

ग्राम पंचायत स्तर पर कहीं-कहीं सिर्फ सरपंचों को शामिल किया गया है लेकिन उनकी रिपोर्ट या शिकायतों का कोई ज्यादा असर नहीं होता।

कही भी ग्राम-सभा की कोई प्रभावी भूमिका देखने या सुनने को नहीं मिली। ग्रामसभा से सामाजिक मूल्यांकन करवाया जाना प्रस्तावित है लेकिन सभी 54 गांवों से यही पता चला कि वहाँ पर राशन की दुकान या सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कभी भी चर्चा नहीं हुयी और नहीं इसका सामाजिक मूल्यांकन किया गया है।

## 16- nplkunkj ds vu||ko

उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यवस्था का सारा दारोमदार दुकानों के संचालन पर निर्भर करता है दुकान के सामान खरीदने वालों का पक्ष तो हमने अभी तक समझा है लेकिन पूरी व्यवस्था के संचालन की समस्या को ठीक से समझने के लिए दुकान, दुकान संचालन की व्यवस्था से जुड़े लोगों का पक्ष समझना भी जरूरी है। सात जिलों के 28 दुकानदारों ने अपने अनुभवों के आधार पर निम्न बिन्दुओं को उठाया-

- खाद्य नियंत्रक का नियंत्रण रहता है।
- राशन लेने वाले कार्डधारकों की संख्या बढ़ गयी है।
- पर्याप्त राशन उपलब्ध नहीं हो पाता।
- लेड सोसाइटी की व्यवस्था से अनाज के परिवहन में आसानी हुयी है।
- गंव के प्रभावशाली लोग अपने दबाव से दुकान चलाना चाहते है जिससे कि गरीबों को दिक्कत होती है।
- शक्कर की कीमत इतनी ज्यादा है कि कोई हमारे यहाँ से शक्कर नहीं खरीदता। इस वजह से हमारी दुकान का मुनाफा काफी कम हो गया है और इस मुनाफे पर दुकान चलाना संभव नहीं हो पाता ।
- आजकल आवंटन काफी विलम्ब से आता है।
- दुकानों को बहुत बड़ा क्षेत्र देखना पड़ता है।

दुकानदारों के अनुसार विगत पांच वर्षों में काफी बदलाव आए हैं और अब उपभोक्ता काफी ज्यादा जागरूक हो गया है। खाद्यान्न की गुणवत्ता भी पहले की तुलना में काफी सुधर गयी है। कुल मिलाकर देखें तो दुकान संचालन में गांवों के दबंगों की भूमिका की वजह से कई दुकानदारों को दिक्कत होती है। अगर राशन की आपूर्ति ठीक न हो तो भी दिक्कत होती है। अंत में राशन की दुकान चलाने वाले की आप और खर्च के पक्ष को भी समझना जरूरी है क्योंकि अगर दुकान चलाने से लाभ कम होगा तो व्यवस्था में या तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा या फिर दुकानों के संचालन में लोग हाथ नहीं डालेंगे।

## 17- v/ ; ; u ds i æ [k fu "d" k]

लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर किए इस अध्ययन से कई तथ्य उभर कर आते हैं।

- मध्यप्रदेश, बिहार और झारखण्ड जैसे राज्यों में अनाजों के आवंटन और उससे जुड़ी इच्छाशक्ति आंध्रप्रदेश या केरल जैसे राज्यों से काफी कमजोर है। यह राज्यों को अनाज के आवंटन और उठाव के आंकड़ों से एकदम स्पष्ट हो जाता है।
- राज्यों के आवंटन के आंकड़े यह बताते हैं कि इस स्तर पर गरीबी और गरीबी रेखा के परिवारों से अलग कोई और ही सिद्धांत काम करता है। अतः मध्यप्रदेश जैसे राज्यों को अपना आवंटन बढ़ाने के लिए केन्द्र से मांग करनी चाहिए। मध्यप्रदेश जैसे राज्यों का आवंटन बढ़ाने में केन्द्र को बहुत दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत से दूसरे राज्यों में अनाज के उठाव के प्रतिशत बहुत कम हैं।
- गांवों में लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन खेती है। खेती के मौसम पर निर्भर होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन में उतार-चढ़ाव आता रहता है जिससे लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा प्रभावित होती है।
- गांवों में रोजगार कार्यक्रमों का लोगों की जरूरत से तालमेल नहीं बैठ पाने की वजह से लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा के लिए गांवों से बाहर पलायन करना पड़ता है।
- लोगों को अनाज की आपूर्ति स्वयं के उत्पादन, मजदूरी के माध्यम से कमाये गये पैसे और अनाज के माध्यम से होती है। पैसे के माध्यम से अनाज उपलब्धता के आधार पर खुले बाजार या उचित मूल्य की दुकान से खरीदा जाता है।
- साल में लगभग 3 से 4 महीने का समय ऐसा है जब गांव के अधिकांश परिवारों के पास अनाज की बहुत दिक्कत होती है।
- यह 3 से 4 महीने वह समय है जब अधिकांश परिवार पलायन की वजह से चाह कर भी अपने राशन कार्ड पर आवंटित अनाज को नहीं खरीद सकते।
- मजदूरी और नगद की अनुपलब्धता के कारण लोग आज भी साहूकार या बड़े किसानों से अनाज उधार लेते हैं। उधारी की यह व्यवस्था उन्हें आगे के महीनों में सस्ता श्रम बेचने को मजबूर करती है।
- एक तरफ गांव में लोगों के पास अनाज की कमी है वहीं मध्य प्रदेश अपने कुल आवंटन का पूरा हिस्सा अनाज नहीं उठा पाता। इसका अर्थ यह है कि अगर सभी गरीब और अंत्योदय के हितग्राही अगर अनाज मांगने आएंगे तो उन्हें अनाज नहीं उपलब्ध करवाया जा सकता।
- जिला स्तर पर अनाज आवंटन और उठाव की स्थिति में बहुत अंतर है और एक दो अपवादों को छोड़कर अधिकांश जिले अनाज के उठाव में बहुत ढीले हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था में लगे लोगों का कहना है कि हितग्राही कम खरीदते हैं इसलिए उठाव कम है। दूसरी तरफ हितग्राही और दुकान संचालक अनाज नहीं मिलने की बात करते हैं।
- सिर्फ 7.3 प्रतिशत हितग्राही यह कहते हैं कि दुकान पूरे महीने खुलती है। 91 प्रतिशत हितग्राहियों के अनुसार दुकान पूरे महीने नहीं खुलती।
- दुकान खुलने का समय तय नहीं है और दुकानदार अपनी सुविधा से दुकान खोलते हैं।
- लगभग 40 प्रतिशत हितग्राही यह बताते हैं कि उन्हें या तो समय से राशन नहीं मिलता या खराब अनाज दिया जाता है।
- जिन जिलों में गरीबी ज्यादा है उन्हीं जिलों में अनाज का उठाव काफी कम है।
- मध्यप्रदेश में अभी भी लगभग 3 लाख अंत्योदय परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है।

- उचित मूल्य की दुकानों पर मिलने वाले चावल की कीमत कई बार सरकार के द्वारा तय दर से अधिक बतायी गयी।
- लगभग 10.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया कि चूँकि उन्हें राशन की दुकान से किशतों में राशन नहीं मिलता इसलिए वे राशन की दुकान पर नहीं जा पाते और अपना पूरा राशन नहीं उठा पाते। यह स्थिति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद है।
- लगभग 65.6 प्रतिशत लोगों को राशन की दुकान और उसमें उपलब्ध वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं रहती। यह भी सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों की अवहेलना है
- 60 प्रतिशत से ज्यादा हितग्राहियों को अनाज के लिए अपने गांव से बाहर जाना पड़ता है और यह दूरी बहुत हद तक कम जानकारी तथा कम पारदर्शिता का कारण बनती है।
- अच्छा अनाज बाजार में बेच देना, कार्ड धारकों से दुर्यवहार करना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से काफी कार्ड धारक दुकान जाना ही नहीं पसंद करते हैं।
- सभी जिलों के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि दुकान और जनपद पंचायत के स्तर पर या तो निगरानी समितियां गठित ही नहीं हैं और अगर हैं तो एक दम निष्क्रिय हैं। जिले के स्तर पर समितियां गठित हैं लेकिन उनका जिला पंचायत और उसके प्रतिनिधियों से कोई तालमेल नहीं है।

कुल मिला कर देखे तो यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था में पहले की अपेक्षा सुधार तो आया है लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ और दिक्कतें हैं। पंचायतों की कम भागीदारी और सामाजिक अंकुषण का न होना व्यवस्था को कमजोर बनाए रखने में मदद करते हैं।

## 18- I pko

अध्ययन के दौरान लोगों से चर्चा के दौरान लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वहीतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए। यह सुझाव इस प्रकार हैं-

- खाद्यान की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए।
- उचित मूल्य की दुकान नियमित रूप से खोली जाएं।
- खराब अनाज मिलने और दुकान समय से न खुलने की स्थिति में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
- राशन की दुकान से किशतों में अनाज मिलने की बात का व्यापक प्रचार हो और अनाज किशतों में मिल सकें यह भी सुनिश्चित किया जाए।
- जिला और जनपद स्तर पर अधिकारियों और संस्थाओं की जवाबदारी तय की जाएं जिससे कि दुकान समय पर खुले।
- तीनों स्तरों पर निगरानी समितियों को सक्रिय बनाया जाए और उनकी भूमिका को स्थानीय संदर्भों के अनुसार परिभाषित किया जाए।
- उचित मूल्य की दुकानों की संख्या को बढ़ाया जाए।
- गरीबी रेखा के लोगों के लिए खाद्यान की कीमत कम की जाएं।
- उचित मूल्य की दुकानों पर केरोसीन की मात्रा समय से उपलब्ध हो और साथ ही उसका प्रति परिवार आवंटन बढ़ाया जाए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि केरोसीन जहां एक तरफ रोशनी का एक मात्र साधन है वहीं आपात स्थिति में और बरसात के मौसम में खाना पकाने का भी एक मात्र साधन है।
- चीनी की कीमत कम की जाएं।
- शिकायतों के निवारण का तंत्र बेहतर और प्रभावी बनाया जाएं।
- उचित मूल्य की दुकानों के प्रबंधन में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की भागीदारी मजबूत करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनायी जाएं।
- ग्राम स्तर पर वार्षिक योजना बने जिसके आधार पर ही उचित मूल्य की दुकान से वस्तुओं की आपूर्ति हो। इसी वार्षिक योजना के आधार पर दुकान का आवंटन तय किया जाए साथ ही इसी योजना के क्रियान्वयन की निगरानी का काम निगरानी समितियों को दिया जाएं।

- जिन महीनों में ग्रामीण परिवार पलायन करके बाहर जाते हैं उस समय उनके कार्ड पर वहीं राशन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बनाई जाए।
- अनाज की कमी या दिक्कत वाले महीनों के लिए विशेष योजना बनाने पर जोर दिया जाए और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के सभी कार्यक्रम इस समय लोगों को काम उपलब्ध करवा सके।
- सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को निश्चित रूप से लागू किया जाए और साथ ही सामाजिक अंकेक्षण के परिणामों को लागू करना सुनिश्चित किया जाए।





























